लखनऊ

रविवार, 24 मई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 268

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

घायल तो यहां हर परिंदा है। मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है.. तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उद्धरण संग्रह बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया।

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

केदारनाथ यात्रा पर मौसम का ब्रेक, देहरादून में वीकेंड पर भारी ट्रैफिक का अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। मौसम विभाग द्वारा तेज हवाओं, बिजली गिरने और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी करने के कारण केदारनाथ यात्रा बाधित हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल तीर्थयात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और खराब मौसम की स्थिति में तीर्थयात्रियों को निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर रोक रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (डीडीएमओ) नंदन सिंह राजवार ने एएनआई को बताया कि हर दो घंटे में जारी की जा रही चेतावनियाँ केदारनाथ तीर्थयात्रा के लिए खतरा साबित हो रही हैं, क्योंकि किसी भी समय भारी बारिश और कोहरे की संभावना है। सेक्टर अधिकारी और सुरक्षा बल तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर रहे हैं, खराब मौसम के दौरान उन्हें रोक रहे हैं और स्थिति में सुधार होने पर ही आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) और जिला प्रशासन भी विमानन सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। खराब दृश्यता और प्रतिकूल मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रहती हैं और उड़ान भरना सुरक्षित होने पर ही परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच, रुद्रप्रयाग स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष केदारनाथ तीर्थस्थल, ट्रेकिंग मार्गों और अन्य यात्रा स्थलों पर लगातार निगरानी रख रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव और राहत दल तैयार हैं। चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब तीर्थयात्रा और गर्मी की छुट्टियों के कारण सप्ताहांत में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए, देहरादून पुलिस ने 24 मई के लिए एक व्यापक यातायात डायवर्जन योजना लागू की है।

एआई वीडियो के जरिए मुझ पर मुकदमा किया गया, मैं 100 मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं'

लखनऊ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के एक कथित विवादित बयान पर प्रदेश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। उनपर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ही गंदी और अमर्यादित टिप्पणी की। लेकिन, अब अपने बचाव में उतरकर अजय राय ने उस विवादित बयान का ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया है और यह दावा किया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना वीडियो है; और आरोप लगाया है कि यह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुके कांग्रेस नेता अजय राय की गाड़ी में बैठे हुए की गई अपनी असंसदीय टिप्पणी पर उन्होंने बिल्कुल ही नया दावा कर दिया है। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि अजय राय अपने समर्थकों से पीएम मोदी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, उन्होंने द हिंदू को बताया है कि वह बीजेपी द्वारा एआई-जेनरेटेड वीडियो है और यह उनकी छवि खराब को करने के लिए किया गया है। उन्होंने अपनी सफाई में आगे कहा, 'मैं 16 साल की एक दलित लड़की के परिजनों से मिलने गया था, जिसने सामंती ताकतों के अत्याचार का सामना किया है, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस की लगातार लड़ाई के डर से बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है।' शुक्रवार को जैसे ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का कथित आपत्तिजनक वीडियो आया, बीजेपी ने अजय राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51 हजार युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा हैं। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'नीदरलैंड की यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, जल, कृषि और उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) पर चर्चा हुई। स्वीडन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल नवाचार में सहयोग पर कई चर्चाएं हुईं। नॉर्वे के साथ, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री सहयोग पर चर्चा आगे बढ़ी है। UAE के साथ रणनीतिक, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर महत्वपूर्ण समझौते हुए।

इटली के साथ, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी पर समझौते हुए।।। इन सभी समझौतों से भारत के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।।।'

पीएम ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे देश के युवाओं को वैश्विक अनुभव मिले।

अब तक लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं

सरकार के मुताबिक, जब से यह पहल शुरू हुई है, तब से पूरे भारत में आयोजित 18 रोज़गार मेलों के ज़रिए अब तक लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। रोज़गार मेला कार्यक्रम सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने और देश भर के युवाओं को रोज़गार के मौके देने के लिए शुरू किया गया था।

बता दें कि 'रोजगार मेला' सरकार की एक बड़ी पहल है। इस पहले के जरिए अबतक 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश भर में अबतक 18 रोजगार मेले आयोजित हुए हैं।

कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार युवाओं के भविष्य को मज़बूत करने और नियमित भर्ती मुहिमों के ज़रिए ज़्यादा मौके पैदा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। PM मोदी ने X पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'देश भर में हमारे युवा साथियों के उज्ज्वल भविष्य और सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इसी दिशा में, कल सुबह 11 बजे, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक और रोज़गार मेले में हिस्सा लूँगा। वहाँ मुझे अलग-अलग सरकारी विभागों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिलेगा।'

इन विभागों में होती है नियुक्ति

देश भर से चुने गए ये युवा भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। इनमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और अन्य विभाग शामिल हैं। बता दें कि SSC, RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड), और IBPS (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान) जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाता नए भर्ती हुए लोग अहम सरकारी विभागों में शामिल हुए। चुने गए उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया गया है। इनमें रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा और वित्तीय सेवाएँ वगैरह शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती हुए लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों से चुना गया है। अब वे अलग-अलग सरकारी दफ़्तरों और संगठनों में अपना काम शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने नए नियुक्त उम्मीदवारों को संबोधित भी किया। उन्होंने रोज़गार पैदा करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर सरकार के ज़ोर के बारे में बात की।

गडकरी का बड़ा दावा- अब 25 वाले ईंधन से ही दौड़ेगी

नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारे देश में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल हैं। परिवहन मंत्री के तौर पर उन्हें इस बात की खुशी है कि देश में अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, बस, ट्रक और यहां तक कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं रहे, बल्कि वे देश के लिए ऊर्जा और ईंधन भी पैदा कर रहे हैं।

गडकरी ने अपनी गाड़ी का उदाहरण देते हुए बताया, 'आज मैं जिस गाड़ी से आया हूं, वह 100 प्रतिशत बायो-इथेनॉल से चलती है। इथेनॉल की कीमत अभी 65 रुपये प्रति लीटर है। खास बात यह है कि यह गाड़ी चलते समय 60 प्रतिशत बिजली

भी बनाती है।' मंत्री गडकरी ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से इसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पेट्रोल और डीजल से इसकी तुलना की जाए, तो गाड़ी चलाने का असल खर्च करीब 25 रुपये प्रति लीटर ही आता है। यह ईंधन सस्ता है, पूरी तरह स्वदेशी है और आयात को कम करने के साथ-साथ प्रदूषण भी नहीं फैलाता। उन्होंने बताया कि ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां जल्द ही बड़े पैमाने पर बाजार में उतारी जाएंगी। गडकरी ने यह भी कहा कि इस साल पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मारुति सुजुकी 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाली अपनी गाड़ियां लॉन्च करेगी। अभी टोयोटा, टाटा, महिंद्रा और सुजुकी जैसी कुल 12 कंपनियों ने ऐसे वाहन बाजार में उतार दिए हैं। इसके अलावा, टू-व्हीलर भी बाजार में आ चुके हैं।

विदेशों से खरीदते हैं 87 प्रतिशत ईंधन

गडकरी ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल कम करने की अपील की। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि हम अपनी जरूरत का 87 प्रतिशत ईंधन दूसरे देशों से मंगाते हैं। बाहर से आने वाला यह ईंधन देश में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि इससे हमारा आयात भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है।

मल्लिकार्जुन खरगे का भाजपा पर तीखा हमला, 'जनता की कमाई किश्तों में लूट रही मोदी सरकार'

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी करने पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी आम आदमी की कमाई को किश्तों में लूट रही है। कीमतों में हुई इस नवीनतम बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए खर्गे ने कहा कि अतीत में जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, तो केंद्र सरकार ने नागरिकों को इसका पूरा लाभ नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौते के तहत काम कर रहे हैं।

खरगे ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये के पार पहुंच गई है। इस बार तो जनता

की कमाई को किश्तों में लूटा जा रहा है! पेट्रोल-डीजल पर प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपये का केंद्रीय कर लगाने के बाद भी भाजपा की भूख शांत नहीं हुई है। जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम थीं, तो उन्होंने इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया - बल्कि उन्हें बेरहमी से लूटा। जब संकट आया, तो वे सीधे चुनाव में कूद पड़े, और चुनाव के बाद त्याग का उपदेश देने लगे। प्रशासन के इस दावे का खंडन करते हुए कि भारत में ईंधन की कीमतें विदेशी देशों की तुलना में कम हैं, खरगे ने इस बात का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सरकारों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के आर्थिक प्रभाव से नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाए। उन्होंने लिखा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ा और प्रधानमंत्री मोदी हम भारतीयों को 'सब ठीक है' का दिलासा देने में व्यस्त थे, तब अन्य देश अपने नागरिकों को राहत दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1. इटली ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम किया, जिससे वहां के लोगों को कुछ राहत मिली। 2. ऑस्ट्रेलिया ने उत्पाद शुल्क कम किया, जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमतें लगभग 17 रुपये प्रति लीटर कम हो गईं। 3. जर्मनी ने तेल पर कर कम किया, जिससे ईंधन की कीमतें 17-19 रुपये प्रति लीटर कम हो गईं। 4. ब्रिटेन ने परिवारों को तेल सहायता के रूप में 100 पाउंड दिए और ईंधन और बिजली पर कर कम किए। 5. आयरलैंड के 250 मिलियन यूरो के राहत पैकेज से पेट्रोल की कीमतें लगभग 0.15 यूरो प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 0.20 यूरो प्रति लीटर कम हो गईं।

नीट यूजी 2026 – रिफंड पोर्टल खुला, 27 मई तक छात्र जमा कर सकेंगे बैंक डिटेल

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को आयोजित रद्द हुई नीट-यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए रिफंड सुविधा शुरू कर दी है। छात्र अब परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण जमा कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नीट-यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर रिफंड का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं और रिफंड प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित रिफंड लिंक पर जा सकते हैं। रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को खाताधारक का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित आवश्यक बैंकिंग विवरण प्रदान करने होंगे। उम्मीदवारों के पास जमा की गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई प्रति अपलोड करने का विकल्प भी है।

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एक बार बैंक विवरण जमा हो जाने के बाद, उन्हें अंतिम माना जाएगा और बाद में कोई सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि जमा करने से पहले सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सत्यापित कर लें। रिफंड के लिए बैंक विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई रात 11:50 बजे तक है।

10 दिन में तीसरी बार बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक संकट के बीच देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस बार पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई हैं। पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर, कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का भाव 92.49 रुपए प्रति लीटर है।

दिल्ली के अलावा, नई बढ़ोतरी के बाद मुंबई में 108.49 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 110.64 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 105.31 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है।

वहीं, मुंबई में डीजल का रेट 95.02 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में 96.98 रुपए प्रति लीटर और कोलकाता में 97.02 रुपए प्रति लीटर है।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पिछले 10 दिन में ईंधन की दरों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई को ही सरकारी तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का बोझ धीरे-धीरे ग्राहकों पर डालना शुरू किया था। 15 मई को कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद 19 मई को 80 पैसे से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंची थी।

देश के विभाजन के समय संघ की शक्ति उतनी नहीं थी अन्यथा देश का विभाजन भी नहीं होता : सुनील आंबेकर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि 1942 से 1947 के बीच दिल्ली एवं सम्पूर्ण पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तेजी से तथा बहुत गहराई से विस्तार हुआ। बड़ी संख्या में लोग संघ के साथ जुड़कर कार्य करने लगे तथापि देश के विभाजन के समय संघ की शक्ति उतनी नहीं थी अन्यथा देश का विभाजन भी नहीं होता। वह दिल्ली में शुक्रवार 22 मई 2026 को इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रस्तुत डाक्यूमेंट्री "दिल्ली में संघ यात्रा" के प्रदर्शन के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जैसा डॉक्यूमेंट्री में भी प्रस्तुत किया गया उस समय श्री गुरुजी का निर्देश था कि विभाजन के बाद जो नया पाकिस्तान बन गया, उस क्षेत्र में जो हिंदू हैं उनकी पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति सुरक्षित रूप से आने तक स्वयंसेवक डटे रहें। इस कार्य में कितने अनगिनत स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ, कितने लोगों को कष्ट हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं है। विस्थापितों के लिए बहुत सारे कैंप्स लगाए गए उसमें कई लाखों लोग रहे। अगस्त 1947 के पहले पखवाड़े में जहाँ यहाँ सारी उथल-पुथल में सब लोग व्यस्त थे, तब श्री गुरुजी कराची में थे और उधर सारे स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से हिन्दू समाज की सुरक्षा का यह सारा कार्य किया जाए।

आंबेकर ने कहा कि अगर संघ, डॉक्टर हेडगेवार जी को राजनीति करनी होती तो वह एक नया राजनैतिक दल शुरू कर देते। लेकिन उन्हें तो समाज को खड़ा करना था, पूरे समाज के में एक सांस्कृतिक जागरण करना था। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। और समाज की सेवा, समाज का उत्थान, समाज को एक मजबूती के साथ खड़े करना, एक पूरे राष्ट्र को अपनी स्वयं के बल पर एक आत्मविश्वास के साथ खड़े करना, यही उसका उद्देश्य था।

सुनील आंबेकर ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का शुभारंभ संघ का प्रारंभिक काल में ही हो गया था। स्वयं आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने संघ की स्थापना की, उनके समय काल में ही दिल्ली में संघ कार्य प्रारंभ हुआ था। इसलिए संघ के 100 साल के इतिहास से दिल्ली का संघ कार्य बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है।

जम्मू-कश्मीरके राजौरी में भीषण एनकाउंटर, 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने का शक, सुरक्षाबलों ने घेरा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राजौरी के दोरिमाल जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। कम से कम 2-3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है और बाकी आतंकवादियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरू हो गई।

इस साल फरवरी में भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर ने किश्तवार से आतंकी नेटवर्क के खात्मे की घोषणा की थी। भारतीय सेना ने सात आतंकवादियों की तस्वीरें पोस्ट की थीं। पोस्ट में लिखा था, ₹326 दिनों के बाद किश्तवार में आतंकी नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया है। पोस्ट में बताया गया था कि मारे गए आतंकवादियों में जैश कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था, जो किश्तवार आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। व्हाइट नाइट कोर ने यह भी कहा था कि उनके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना खुफिया एजेंसी भी किश्तवार में शामिल थीं।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

पिछले सप्ताह, इस्लामाबाद को दिए गए एक कड़े सैन्य संदेश में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ़ गतिविधियाँ जारी रखना जारी रखता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह भूगोल या इतिहास का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। मानेकशॉ सेंटर में 'यूनिफॉर्म अनवेल्ड' द्वारा आयोजित एक संवाद सत्र में, उनसे पूछा गया कि यदि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थितियाँ फिर से उत्पन्न होती हैं, तो भारतीय सेना क्या प्रतिक्रिया देगी। सेना प्रमुख ने कहा, यदि आपने मुझे पहले सुना है, तो मैंने जो कहा है... वह यह है कि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ़ गतिविधियाँ जारी रखना जारी रखता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह भूगोल या इतिहास का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। 'सेना संवाद' नामक इस कार्यक्रम में उनकी ये टिप्पणियाँ देश और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाने के कुछ दिनों बाद आईं। जनरल द्विवेदी की संक्षिप्त टिप्पणी में पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश था और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ़ भारत के रुख को दोहराया।

'बेटी ने लव मैरिज कर ली...' मुरादाबाद में पिता ने जहर खाकर दे दी जान; मौत की खबर पहुंची, लेकिन अंतिम संस्कार में नहीं आई

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बेटी के प्रेम विवाह से आहत एक पिता ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद भी बेटी और उसका पति अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचे। इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार इलाके का है। यहां रहने वाले एक परिवार की 24 वर्षीय बेटी 14 मई को अचानक घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों के अनुसार युवती का अपनी चाची के भतीजे, यानी रिश्ते के ममेरे भाई, के साथ प्रेम संबंध था। जब परिवार को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय करने की कोशिश शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर युवती घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बाद में दोनों के फिरोजाबाद पहुंचने और शादी करने की जानकारी सामने आई। बेटी के अचानक घर छोड़ने और समाज में हो रही चर्चाओं से पिता गहरे सदमे में चले गए। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया था और लगातार मानसिक तनाव में रह रहे थे। इसी बीच पिता ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पिता की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

परिजनों ने युवती को उसके पिता के निधन की सूचना भी दी, लेकिन आरोप है कि उसने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, युवती और उसका पति अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। गमगीन माहौल में परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी और दामाद की गैरमौजूदगी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्रयागराज में मिली लड़की की लोकेशन

उधर, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवती ने प्रशासन को अपनी शादी की तस्वीरें भेजी हैं और दावा किया है कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस को दोनों की लोकेशन प्रयागराज में मिली है। इसके बाद एक टीम को दोनों को तलाशने के लिए रवाना किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। युवती के बयान दर्ज होने और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी चारू निगम का बड़ा एक्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अपने सख्त और एक्शन वाले अंदाज का परिचय दिया है। लगातार अपराध नियंत्रण और स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस कर रहीं एसपी ने करौंदी कला थाने में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की तैनाती कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि लापरवाही अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी।

कादीपुर में इंस्पेक्टर क्राइम की जिम्मेदारी संभाल रहे अश्विनी कुमार सिंह को अब करौंदी कला थाने का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं अब तक थाना अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे दरोगा ज्ञानेश दूबे को वलीपुर रिपोर्टिंग चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम लगातार जिले की कानून व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीते दिनों दो दर्जन गोवंशों के मृत मिलने की घटना के बाद से पुलिस महकमे में लगातार हलचल बनी हुई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जा रही है। एसपी के नेतृत्व में सुलतानपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। हाल के दिनों में कई बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए, जिससे अपराधियों में खौफ और आम जनता में भरोसा बढ़ा है। तेज कार्रवाई और त्वरित निर्णय क्षमता के चलते पुलिस अधीक्षक चारू निगम की कार्यशैली जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

गंगा एक्सप्रेस-वे पर कपड़ों से भरा कैंटर पलटा, चालक-परिचालक घायल

आर्यावर्त संवाददाता

हापुड़। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शंकराटीला क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह करीब छह बजे कपड़ों से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार कैंटर दिल्ली से कपड़े लेकर संभल जा रहा था। गांव शंकराटीला क्षेत्र में पहुंचते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते कैंटर गंगा एक्स्प्रेसवे पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे चालक सलमान और परिचालक अब्दुल समद, निवासी संभल, को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सीएचसी गढ़ भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में वाहन को नुकसान पहुंचा है, हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि चालक परिचालक मामूली रूप से घायल हुए हैं।

अग्निशमन केंद्र या बंधुआ श्रम शिविर

सुल्तानपुर। जिस वर्दी को आपदा में लोगों की जान बचाने के लिए पहनाया गया, उसी वर्दी से अब झाड़ू लगवाई जा रही है। अग्निशमन केंद्र में तैनात होमगार्ड जवानों से सुरक्षा ड्यूटी छोड़ कबाड़ ढुलवाने, पाइप फैलाने, परिसर की सफाई और मजदूरों जैसे काम कराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ जवान जब झाड़ू-पोछा करते दिखे, तो लगा मानो अग्निशमन केंद्र नहीं, कोई ठेकेदार का गोदाम चल रहा हो। जिन हाथों को आग बुझाने और आपदा से लड़ने के लिए तैयार किया गया, उन्हीं हाथों में अब झाड़ू और कबाड़ थमा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि जवान वर्दी में कम और मुफ्त के मजदूर ज्यादा नजर आ रहे हैं। विभागीय दबाव इतना कि जवान चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। सवाल यह है कि क्या सरकार ने होमगार्डों की भर्ती आग से लड़ने के लिए की थी या अफसरों की निजी व्यवस्था संभालने के लिए।

पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला, अजय राय और 30 समर्थकों पर एफआईआर, अधिवक्ता ने सौंपी 'पेन ड्राइव'

आर्यावर्त संवाददाता

महोबा. महोबा जिले में अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा से मिलने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य और अधिवक्ता नीरज रावत की तहरीर पर अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव बृजराज सिंह समेत 30 समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवती महोबा में किराये का कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल को वह लाइब्रेरी से घर लौटते समय लापता हो गई थी। 16 दिन बाद युवती को पुलिस ने बरामद किया था। युवती ने आरोपियों पर अपहरण, दुष्कर्म व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में युवती

का शादी करते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ।

पीएम के खिलाफ अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं

इसमें स्वेच्छा से विवाह किए जाने जैसे तथ्य दिखाई दिए। इसके बाद से यह मामला बदलता नजर आने लगा। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोबा पहुंचे और नीट की तैयारी कर रही छात्रा से पूरी घटना की जानकारी ली। पीड़िता से मिलकर जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं।

15-16 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे अजय राय

प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद भाजपाई आक्रोशित हो गए। अधिवक्ता नीरज रावत ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 22 मई को बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप लगाया कि अजय राय 15-16 गाड़ियों के काफिले और दर्जनों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। वाहनों को सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया। इससे रास्ता बाधित हो गया।

विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज

ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने वायरल वीडियो की पैन ड्राइव पुलिस को साक्ष्य के तौर पर सौंपी। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।

आय से छह गुना अधिक संपत्ति मामले में रिटायर्ड वरिष्ठ लिपिक विजिलेंस के शिकंजे में

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में तैनात रहे सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक भानु प्रताप सिंह पर विजिलेंस का शिकंजा कस गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

मूल रूप से अमेठी जनपद के मुंशीगंज निवासी भानु प्रताप सिंह वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। शासन के निर्देश पर अप्रैल 2023 में उनके वर्ष 1992 से 2020 तक के सेवाकाल के दौरान अर्जित चल-अचल संपत्तियों की जांच कराई गई। अयोध्या सेक्टर की विजिलेंस टीम की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार सेवाकाल में भानु प्रताप सिंह की वैध आय कुल 70 लाख 38 हजार 405 रुपये पाई गई, जबकि इसी अवधि में उन्होंने संपत्ति खरीद, भरण-पोषण और अन्य मदों में 4 करोड़ 39 लाख 28 हजार 884 रुपये खर्च किए। जांच में आय और व्यय के बीच 3 करोड़ 68 लाख 90 हजार 479 रुपये का भारी अंतर मिला, जो उनकी वैध आय से करीब छह गुना अधिक है। विजिलेंस अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान इस अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शासन को रिपोर्ट भेजी गई। शासन ने 20 मार्च 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है।

अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

सुल्तानपुर। अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार को सख्त कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। कार्रवाई तहसीलदार सदर के नेतृत्व में गुप्तारगंज क्षेत्र में की गई।

प्रशासन को सूचना मिली थी कि कूरेभार थाना क्षेत्र के गुप्तारगंज इलाके में बिना अनुमति मिट्टी का खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही तहसीलदार सदर राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिट्टी लदी हुई मिलीं। तहसीलदार की सूचना पर कूरेभार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक चालक को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तहसीलदार सदर ने बताया कि बिना परमिट मिट्टी खनन करना अवैध है और ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा के रोही गांव से गायब हो गया था गोपाल, अब बंद घर में मिली उसकी लाश, मचा हड़कंप

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रोही गांव में 15 वर्षीय किशोर के शव मिलने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। किशोर का शव एक बंद पड़े मकान में संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई हैं।

मृतक की पहचान गोपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, गोपाल कुछ समय पहले घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव के एक बंद पड़े मकान में एक किशोर का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान गोपाल के रूप में की।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बताया जा रहा है कि शव पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है। परिजनों का आरोप है कि गोपाल की हत्या कर शव को सुनसान मकान में फेंका गया। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में भी दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि किशोर की आखिरी गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके।

क्या कहती है पुलिस?

एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का गिरफ्तार की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे संदिग्ध हालत में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी

सुल्तानपुर। जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना चांदा थाना क्षेत्र के कालिकागंज चौराहे के पास ग्राम बैतीकला के समीप की है। शुक्रवार को सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है, जो क्षेत्र में कबाड़ बीनकर अपना जीवन यापन करता था। हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।

...जब आइटीबीपी जवान के मां की जिंदगी पर बात आई, हथियारबंद कमांडो ने कानपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय को घेर लिया

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। आइटीबीपी के कांस्टेबल विकास सिंह की मां का उपचार के दौरान हाथ कटने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट से नाराज आइटीबीपी जवानों ने शनिवार सुबह पुलिस आयुक्त कार्यालय घेर लिया।आइटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद और लाइजनिंग अफसर अर्पित पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर कार्रवाई करने को लेकर बात की।

महाराजपुर स्थित 32 बटालियन के अइटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी को सांस की परेशानी पर 13 मई को टाटमिल स्थित कृष्णा हास्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उपचार के दौरान उनका हाथ काला पड़ गया था, जिसमें संक्रमण फैलने की वजह से उन्हें यहां से पारस हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा था।

20 मई को विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर इंसाफ के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। पुलिस आयुक्त ने प्रकरण में सीएमओ से जांच रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस आयुक्त के अनुसार, जांच रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पूरी रिपोर्ट संभावनाओं पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि हाथ का इंन्फेक्शन धर्मा एम्बोलिज्म की वजह से हौ सकता है।

एम्बोलिज्म का मतलब है खून का थक्का बनना। यह स्थिति कैसे बनी, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। इस रिपोर्ट को देख आइटीबीपी के अफसर भी नाराज हो गए। उन्होंने सीएमओ की गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम पर अस्पताल प्रबंधन और डाक्टरों को बचाने का आरोप लगाया। शनिवार को कमांडेंट और 50 से अधिक जवानों में पुलिस आयुक्त कार्यालय घेर लिया।

कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया था। आइटीबीपी के कमांडेंट ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था विपिन ताडा से मिले। इसके बाद आधे से ज्यादा जवान गाड़ियों से परिसर के बाहर चले गए। लगभग एक घंटे से कमांडेंट समेत अफसर अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा से बात चल रही है।

झोपड़ियों पर जब आसमान गिर रहा आज, कैसे महलों के गीत भला कवि गायेगा : जटायु

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कटका क्लब सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता आशुकवि मथुरा प्रसाद सिंह जटायु व संचालन हरिनाथ शुक्ल हरि ने किया। नरेंद्र शुक्ल ने वाणी वंदना से कवि सम्मेलन की शुरुआत की । अमेठी के अजय जायसवाल अनहद ने सुनाया- छालों से भरे पांव तो घुटने के बल चलो ,डिग्री जला के मौत के फंदे न चढ़ो तुम । कवि अभिजीत त्रिपाठी की पंक्तियां थीं - मैं राजधर्म आदर्शों का आयाम नहीं बन पाऊंगा ,तुम सीता न बनो प्रिये मैं राम नहीं बन पाऊंगा। राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि ने दोहा सुनाते हुए कहा - राजनीति के गर्भ से निकली ऐसी चीख, लोकतंत्र है मर गया जनता मांगे भीख । उनके चर्चित कविता की पंक्तियां थीं - हो गया काफी समय सत्ता सम्भाले आपको, मेरे साहब अब तो अपनी जुमले बाजी छोड़िये। अध्यक्षता कर रहे आशुकवि मथुरा प्रसाद सिंह जटायु ने सुनाया - झोपड़ियों पर जब आसमान गिर रहा आज, कैसे महलों के गीत भला कवि गायेगा । कवियों लेखनी संभालो वाणी मुखर करो, देखो सारा जग अनुगामी बन जायेगा।

रोहित राय ने ठहर जाओ नहीं जाओ मेरे दिल ने पुकारा है। मेरी दुनिया मेरे हमदम मेरा सबकुछ तुम्हारा है सुनाकर वाहवाही बटोरी।कवयित्री कान्ति सिंह ने हे रामा फिर से आई जाए बचपनवा कविता पढ़ी ।सर्वेश कांत वर्मा सरल ने सुनाया शायद मेरे लिए वो कमाल निकलेंगे,मेरे दर्द में पेरासिटामोल निकलेंगे । जिनसे मांगा मैंने जख्म में मरहम, क्या पता वो दर्द के दलाल निकलेंगे। संचालक हरिनाथ शुक्ल हरि ने सुनाया दीप बन कर जलो जिंदगी में सदा, मेरे दीवाने दिल की यही है दुआ । कवि नरेन्द्र शुक्ल की पंक्तियां थीं-तन्त्र जिनकी मुट्ठियों में कैद था ,डर रहे हैं आज चौकीदार से। कवि सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज प्रतिनिधि त्रिनेत्र पाण्डेय, सुनीता श्रीवास्तव, नफीसा खातून, सत्यम चौरसिया, कमल नयनम तिवारी, रजनीश, वीर विक्रम सिंह आदि कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर इन्द्रेश कौशिक महराज, संस्था के संरक्षक राजकुमार मिश्र व प्रदेश प्रभारी डॉ ऋषभदेव शुक्ल ने अंगवस्त्र, पुष्पमाला व प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों का अभिनंदन किया।

श्रमिक कल्याण और रोजगार सृजन को और प्रभावी बनाने के निर्देश, 'बाल श्रमिक विद्या योजना' सभी 75 जनपदों में होगी लागू

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित पहलों की समीक्षा करते हुए श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को अधिक व्यापक तथा परिणामोन्मुखी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में 'बाल श्रमिक विद्या योजना' को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, 'सेवामित्र व्यवस्था' को और अधिक प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए आधुनिक सुविधा केन्द्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे और बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए। साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसे बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए।बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2020 में शुरू की गई 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के अंतर्गत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्तमान में यह योजना 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने नए प्रावधानों के साथ इसे सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए इसे और अधिक प्रभावी व जनोपयोगी बनाने की बात कही। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिक मोबाइल अनुप्रयोग, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेंटर के जरिए घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल पर 1,097 सेवा प्रदाता, 5,049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग में हुए संस्थागत सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं। मार्च 2017 तक यह संख्या 14,176 थी, जबकि अप्रैल 2017 के बाद 18,407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,860 कारखानों का पंजीकरण किया गया। विभाग को बीआरएपी के क्रियान्वयन में 'टॉप अचीवर' की मान्यता प्राप्त हुई है तथा उद्योग समागम 2025 में श्रम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केन्द्रों यानी 'लेबर अड्डों' को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों को केवल श्रमिकों के एकत्रीकरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि श्रमिक सहायता एवं सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। दूसरे क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। बैठक में जानकारी दी गई कि विष्णुपुरी स्थित भूमि पर 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है, जहां बढ़ईगिरी, विद्युत कार्य, फिटर, प्लम्बर, पेंटर और भवन निर्माण सहित विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेनाझाबर स्थित भूमि पर 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला छात्रावास भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताते हुए कहा कि युवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में बताया गया कि जुलाई 2025 में गठित 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के माध्यम से देश और विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। रोजगार मिशन को विदेश मंत्रालय से भर्ती एजेंसी का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में आयोजित रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से 27,555 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें 2,300 युवाओं का चयन विदेशों में रोजगार के लिए हुआ।

मेरठ में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर बड़ी कार्रवाई, अधिशासी अभियन्ता योगेश कुमार निलंबित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने मेरठ में लगातार विद्युत लाइनों में खराबी और आपूर्ति बाधित होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियन्ता योगेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर विभागीय कार्यों में लापरवाही, उच्चाधिकारियों को समय पर सूचना न देने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया है।कारपोरेशन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, 19 मई 2026 को शाम 5:47 बजे 132 केवी मोदीपुरम-द्वितीय कंकड़खेड़ा लाइन ट्रिप हो गई थी, जिसमें टावर संख्या 33 और 34 के बीच कंडक्टर टूट गया। इसके अगले दिन 20 मई को सुबह 7:51 बजे 132 केवी मोदीपुरम-द्वितीय बेदव्यासपुरी लाइन भी ट्रिप हुई, जिसमें टावर संख्या 8 और 9 के बीच मिड स्पैन ज्वाइंट से कंडक्टर टूट गया।

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना मदेयगंज पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को राजधानी अस्पताल के पास पुराने पक्के पुल के निकट से दबोचा। मामले में पीड़िता पहले ही सकुशल बरामद होकर थाने पहुंच चुकी थी।पुलिस के अनुसार, 19 मई 2026 को वादी द्वारा थाना मदेयगंज में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि उसकी करीब 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मदेयगंज में तत्काल मुकदमा संख्या 0063/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक दिनेश कुमार चौबे द्वारा की जा रही थी।घटना के बाद पुलिस टीम ने किशोरी और आरोपी की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संभावित ठिकानों पर लगातार तलाश और सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में 22 मई 2026 को मामले से संबंधित किशोरी स्वयं थाना मदेयगंज पहुंच गई, जिसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया और 23 मई 2026 को उपनिरीक्षक दिनेश कुमार चौबे अपनी टीम के साथ तलाश में जुटे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद उमर पुत्र मुजीब अहमद निवासी बाबा का पुरवा, मशालची टोला, खदरा, थाना मदेयगंज को राजधानी अस्पताल, पुराने पक्के पुल के पास से दोपहर करीब 12:40 बजे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपी को उसके विरुद्ध दर्ज अपराध की जानकारी देते हुए हिरासत में लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थाना क्षेत्रों और इकाइयों से जुटाई जा रही है।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक दिनेश कुमार चौबे, मुख्य आरक्षी तुफैल अहमद तथा आरक्षी अवधेश कुमार शामिल रहे।

ऑटो में टप्पेबाजी कर जेवर उड़ाने वाला अंतर्जनपदीय गिरोह गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में ऑटो और टेंपो में बैठने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर टप्पेबाजी करने वाले एक शातिर अंतर्जनपदीय गिरोह का कृष्णानगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए आभूषण, नगदी और वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद किया है। गिरोह के सदस्य भीड़भाड़ वाले चौराहों और मेट्रो स्टेशनों के आसपास यात्रियों को भ्रमित कर उनके जेवर और कीमती सामान चोरी कर लेते थे।पुलिस के अनुसार, 20 मई 2026 को सरोजनीनगर निवासी कृष्णा मिश्रा की तहरीर पर थाना कृष्णानगर में मुकदमा संख्या 219/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में अवध चौराहे पर ऑटो में बैठी अज्ञात महिलाओं द्वारा टप्पेबाजी कर सामान चोरी किए जाने की बात कही गई थी। इसी प्रकार 22 मई को उन्नाव निवासी रामकुमारी तथा चिनहट निवासी बबली भारती की शिकायत पर भी अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए।लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने और मामलों के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में चार विशेष टीमों का गठन किया गया। साथ ही एक टीम को सादे वस्त्रों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी के लिए लगाया गया। सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर की निगरानी में गठित टीमों ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।इसी क्रम में 23 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डूडा कॉलोनी, आशाराम बापू मार्ग से गिरोह की सरगना बिंदु उर्फ चिंकी, गीता देवी और नरसिंह को गिरफ्तार कर लिया।

गोमतीनगर कोचिंग डिपो को एक साथ चार आईएसओ प्रमाण-पत्र, जापानी 5एस प्रमाणन भी मिला

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोमतीनगर कोचिंग डिपो (कैरेज एंड वैगन) ने यात्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक साथ चार आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डिपो में यात्री कोचों का अनुरक्षण, सुरक्षा जांच और स्वच्छता सुनिश्चित की जाती है।डिपो को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001, पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईएसओ 14001, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001 तथा ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ 50001 प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं।इसके साथ ही डिपो को जापानी 5एस प्रमाणन (छंटाई, सुव्यवस्थित रखना, स्वच्छता, मानकीकरण और निरंतरता) भी प्राप्त हुआ है। यह कार्यस्थल को व्यवस्थित, स्वच्छ और अधिक दक्ष बनाने की जापानी कार्यप्रणाली है, जिसका उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना, समय की बचत करना और अपशिष्ट को कम करना है।इस उपलब्धि पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि यह डिपो की टीम की मेहनत, अनुशासन और गुणवत्ता के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य जारी रहेगा।

आईसीएआई लखनऊ शाखा का भव्य कॉन्वोकेशन सम्पन्न, नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ सम्मान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल (सीआईआरसी) की लखनऊ शाखा द्वारा "कॉन्वोकेशन – मई 2026" का भव्य एवं गरिमामयी आयोजन हॉलीडे इन, लखनऊ एयरपोर्ट में सम्पन्न हुआ। समारोह में नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित करते हुए उनके पेशेवर जीवन की नई शुरुआत का उत्सव मनाया गया।आईसीएआई के मेंबर्स एवं स्टूडेंट्स सर्विसेज डायरेक्टरेट के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में बड़ी संख्या में नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके अभिभावक, परिवारजन, वरिष्ठ सदस्य तथा गणमान्य अतिथि शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, गर्व और प्रेरणा से परिपूर्ण दिखाई दिया।समारोह में केंद्रीय परिषद सदस्य ज्ञान चंद्र मिश्रा, सीआईआरसी के अध्यक्ष अंकुर गोयल, आईसीएआई लखनऊ शाखा के अध्यक्ष अश्वनी जायसवाल तथा सचिव आशीष गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त शाखा के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई।अपने संबोधन में वक्ताओं ने नव-योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बधाई देते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि नैतिकता, अनुशासन, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने युवा पेशेवरों को लगातार सीखने, नई तकनीकों में दक्षता विकसित करने और पेशेवर उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों और युवाओं के लिए अवसरों का बड़ा माध्यम, निवेश बढ़ाने पर जोर : केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किसानों, उद्यमियों और युवाओं के लिए अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का भी प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इस क्षेत्र को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।उप मुख्यमंत्री ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों और प्रोत्साहनों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।इसी क्रम में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी. एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित अप्रेजल समिति की बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न निवेशकों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन पर विभागीय अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने विस्तृत चर्चा की।बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त छह नए प्रस्तावों को अप्रेजल समिति के समक्ष रखा गया। परीक्षण के दौरान एक प्रस्ताव अपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया, जबकि पांच प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के साथ राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।संस्तुत परियोजनाओं में कानपुर देहात में कार्बोनेट वाइन निर्माण इकाई, मुजफ्फरनगर में ऑर्गेनिक गुड़ क्यूब्स तथा ब्राउन और व्हाइट शुगर इकाई, एटा में चिकोरी प्रसंस्करण इकाई, बाराबंकी में फ्रोजन फूड्स एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई तथा हाथरस में कुट्टू और सौंफ प्रसंस्करण इकाई की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।बैठक में संबंधित इकाइयों को स्थानीय किसानों से प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही निवेशकों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य आवश्यक तकनीकी अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए कहा गया।अपर मुख्य सचिव बी. एल. मीणा ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से कृषि आधारित उद्योगों को गति मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

संक्षेप

भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बड़ा फैसला, लखनऊ में बिजली अधिकारियों-कर्मचारियों को बायोमैट्रिक उपस्थिति में राहत

लखनऊ। ग्रीष्म ऋतु के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली व्यवधानों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिल) ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। लखनऊ जनपद में कार्यरत बिजली विभाग के अभियंताओं और संविदाकर्मियों को 30 जून 2026 तक बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमों में अस्थायी राहत प्रदान की गई है।मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) राजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, मई-जून 2026 की भीषण गर्मी और बढ़ी बिजली मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना तथा किसी भी विद्युत व्यवधान की स्थिति में उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना बताया गया है।जारी निर्देशों के तहत लखनऊ जनपद में कार्यरत सभी अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता और संविदाकर्मियों को यह छूट दी गई है कि वे अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अलावा 24 घंटे के अंतराल में एक बार अपने संबंधित जोन के किसी भी कार्यालय या बिजली उपकेंद्र से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। इससे फील्ड में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को आपूर्ति व्यवस्था संभालने और शिकायतों के त्वरित समाधान में सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।कार्यालय ज्ञाप में कहा गया है कि ग्रीष्मकाल के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्मचारियों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पारंपरिक उपस्थिति नियमों में अस्थायी शिथिलता देकर फील्ड स्तर पर कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।इस संबंध में सभी मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशों से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली संचालित करने वाली संस्था वाइब्रेंट इन्फो सॉल्यूशन, लखनऊ को भी अटेण्डेंस ऐप और सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के इस निर्णय को गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को कम से कम व्यवधान का सामना करना पड़े।

अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत, दुबग्गा क्षेत्र में हादसे के बाद चालक फरार

लखनऊ। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। छन्दोईया ईदगाह के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात डाला वाहन ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान ट्रामा सेंटर में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार सुबह लगभग 8 बजे से 8:30 बजे के बीच की है। थाना दुबग्गा क्षेत्र के छन्दोईया ईदगाह के सामने स्थित पेट्रोल पंप के निकट एक तेज रफ्तार अज्ञात डाला वाहन ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो चालक मोहम्मद कलीम पुत्र लड्डन, निवासी नवीं पनाह नगर, थाना माल, जनपद लखनऊ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी उम्र करीब 37 वर्ष बताई गई है।हादसे के बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल घायल चालक की मदद की और एंबुलेंस बुलाकर उन्हें ट्रामा सेंटर, लखनऊ भिजवाया। चिकित्सकों द्वारा इलाज शुरू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मोहम्मद कलीम की जान नहीं बचाई जा सकी और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।घटना की सूचना मिलते ही दुबग्गा पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल जाकर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस अब दुर्घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात डाला वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वाहन की पहचान कर आरोपी चालक तक पहुंचा जा सके।

भीषण गर्मी में जून में परीक्षाएं कराना छात्र हित में नहीं, शेष सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित हों : डॉ अमित कुमार राय

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ अमित कुमार राय ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जून माह में सेमेस्टर परीक्षाएं कराए जाने पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के स्वास्थ्य को देखते हुए अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं जून माह में आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए।डॉ अमित कुमार राय ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षाएं 15 मई तक संपन्न कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कई विश्वविद्यालय अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई जनपदों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे विषम मौसम में जून के दौरान परीक्षाएं आयोजित करना छात्र और शिक्षक हितों के साथ अन्याय होगा।उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजे पत्र में मांग की है कि विश्वविद्यालयों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य शेष परीक्षाओं को जून माह में कराने से रोका जा सके। उनका कहना है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।डॉ अमित कुमार राय ने यह भी कहा कि प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में पंखे और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी के बीच परीक्षा केंद्रों पर बैठकर परीक्षा देना छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।उन्होंने ग्रीष्मावकाश के दौरान परीक्षाएं आयोजित किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

अंग्रेजी शराब की दुकान में बड़ी चोरी, ग्रिल तोड़कर 50 से 60 पेटी शराब पार, सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए बदमाश

लखनऊ। राजधानी के चंद्रिका देवी रोड स्थित भवानीपुर क्षेत्र में एक कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान के पीछे लगी लोहे की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और लगभग 50 से 60 पेटी शराब चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर डीवीआर भी अपने साथ ले गए।पुलिस के अनुसार, भवानीपुर स्थित कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान मनीष कुमार जायसवाल के नाम पंजीकृत है। रोजाना की तरह 22 मई की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर कैशियर द्वारा बिक्री का हिसाब-किताब लिया गया। दुकान पर सेल्समैन लवकुश यादव और अनिरुद्ध कुमार के साथ मैनेजर हर्ष जायसवाल और विवेक सिंह कार्यरत हैं।

बिजली कर्मियों की लगातार मौतों और हादसों पर संविदा कर्मचारी संघ नाराज, प्रबंध निदेशक को सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में लगातार हो रही संविदा और निविदा कर्मचारियों की मौतों तथा गंभीर हादसों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने गहरी चिंता जताई है। संघ ने प्रदेशभर में विद्युत उपकेंद्रों पर कार्य के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हुए प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि अप्रैल और मई 2026 के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य के दौरान कई संविदा और अकुशल श्रमिकों की जान चली गई, जबकि कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। संघ ने इन घटनाओं को बिजली विभाग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और श्रमिकों के प्रति लापरवाही का परिणाम बताया है। ज्ञापन के अनुसार, 22 अप्रैल को अयोध्या जनपद के ड्योढ़ी विद्युत उपकेंद्र पर तैनात मातादीन की खंभे से गिरकर मौत हो गई। 23 अप्रैल को संभल जिले के बाहरई विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत ओंकार की बिजली की चपेट में आने से जान चली गई। इसी दिन बिजनौर के चंदक विद्युत उपकेंद्र पर तैनात सुभाष 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। संघ ने यह भी बताया कि मुरादाबाद के कंपनी बाग विद्युत उपकेंद्र पर तैनात सचिन आरएमयू में ब्लास्ट होने से गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि आजमगढ़ के जाफरपुर विद्युत उपकेंद्र पर कार्यरत जय सिंह 33 हजार वोल्ट लाइन का तार गिरने से बुरी तरह घायल हो गए।

अपराधमुक्त राजनीति से ही संभव है नया भारत-विकसित भारत

भारत आज एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर देश विकसित भारत-2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व राजनीति और कूटनीति के केंद्र में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में अपराध, धनबल और बाहुबल की बढ़ती पैठ लोकतंत्र की आत्मा को आहत कर रही है। यह विडंबना ही है कि जिस भारत को विश्वगुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है, उसकी राजनीति अभी भी अपराधमुक्त नहीं हो सकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़ों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लगभग 65 प्रतिशत विधायक आपराधिक मामलों वाले हैं, जबकि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। रिपोर्ट के अनुसार 294 विधायकों में से 190 विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं तथा लगभग 142 विधायकों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अन्य गंभीर मामले भी शामिल हैं।

यह केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं है। संसद और देश की अनेक विधानसभाओं की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में अपराध और दागी छवि वाले लोगों की बढ़ती उपस्थिति आज राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। राजनीति मूलतः लोकसेवा, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम मानी गई थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने राजनीति को मूल्य आधारित दिशा दी। लेकिन समय के साथ राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता का स्थान धीरे-धीरे चुनावी गणित, धनबल और प्रभावशाली समूहों ने लेना शुरू कर दिया। आज कई राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में योग्यता, चरित्र और जनसेवा की बजाय "जीतने की क्षमता" को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दागी छवि वाले व्यक्तियों को भी टिकट देने में संकोच नहीं किया जाता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में आने के बाद अनेक मंचों से राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संसद में और सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा कि राजनीति को अपराधमुक्त बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु चिंता का विषय यह है कि आज भी लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति समान दिखाई देती है। चुनाव जीतने की मजबूरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दल अपराधी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है चुनावों का अत्यधिक खर्चीला होना। आज चुनाव लड़ना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। बड़े संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोग चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा कारण है बाहुबल और प्रभाव का उपयोग। कई क्षेत्रों में आज भी राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा कारण है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण आरोपी चुनाव लड़ते रहते हैं और जनप्रतिनिधि बन जाते हैं।

राजनीति में अपराधीकरण का दूसरा बड़ा पक्ष है धनबल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देती है। संसद और विधानसभाओं में करोड़पति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र धीरे-धीरे सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर होता जा रहा है? यदि राजनीति केवल धनवान और प्रभावशाली वर्गों तक सीमित हो जाएगी तो लोकतंत्र की समावेशी भावना कमजोर होगी। इन परिस्थितियों में नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय मतदाता संगठन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। इसके संस्थापक रिखबचंद जैन के नेतृत्व में लंबे समय से राजनीति को स्वच्छ और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। संगठन मतदाता जागरूकता, नैतिक मतदान, स्वच्छ राजनीति और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि मूल्य आधारित व्यवस्था मानते हुए यह संगठन समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि मतदाता केवल जाति, धर्म, क्षेत्र या दलगत निष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के चरित्र और सार्वजनिक जीवन को देखकर मतदान करें।

आईटी नियम दूसरा संशोधन, 2026: भारत के डिजिटल शासन की ओर एक बड़ा कदम

वैभव गग्गर, सुकाम्या वहल

डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। प्लेटफार्म अब केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं हैं। उनके आकार और एल्गोरिदम उपयोग करने की उनकी क्षमता ने ऑनलाइन नुकसान और लोगों को प्रभावित करने के तरीकों को बदल दिया है।

भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अब लोगों के संवाद करने और जानकारी तक पहुँचते के तरीकों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसने जवाबदेही और ऑनलाइन नुकसान को लेकर नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं और मौजूदा नियामक व्यवस्था को तदनुसार विकसित होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में किए जाने वाले प्रस्तावित बदलाव, जो 30 मार्च, 2026 को प्रकाशित किए गए हैं, भारत की डिजिटल नियामक व्यवस्था में प्रक्रिया से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए एक बड़े कदम को प्रतिबिंबित करते हैं। इन मसौदा संशोधनों का उद्देश्य भाग ढ्ढ के तहत मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण, परामर्श और दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यस्थों के अनुपालन को मजबूत करना और भाग ढ्ढढ्ढ के तहत डिजिटल मीडिया से संबंधित कंटेंट नियमन व्यवस्था की नियामक निगरानी के प्रभाव को बढ़ाना है।

सबसे पहले, नियम 3(1)(जी) और 3(1)(एच) के तहत डेटा रखरखाव की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्टीकरण है। प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट करता है कि रखरखाव आवश्यकताओं से जुड़े नियम; अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित जिम्मेदारियों के अतिरिक्त हैं। इससे वह अस्पष्टता दूर होती है जिसने कभी-कभी मध्यस्थों को अलग-अलग या न्यूनतम अनुपालन दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी है। आईटी अधिनियम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अकेले काम करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया कानून, वित्तीय नियम और केवल उनके उद्योग पर लागू होने वाले नियमों का भी पालन करना होता है। इस अर्थ में, यह स्पष्टीकरण अर्थपूर्ण और आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि संशोधन रखरखाव से संबंधित है, पहुँच से नहीं। ऐसे डेटा का खुलासा कानूनी प्रक्रियाओं और सांविधिक सुरक्षा के अधीन रहता है। हालांकि इस प्रकार की एक सामान्य संरक्षण धारा को इस रूप में पढ़ा जा सकता है कि यह उकसाने वाला, अतिव्यापी या यहाँ तक कि मध्यस्थों द्वारा उपयोगकर्ता डेटा के अनिश्चितकालीन रखरखाव के बारे में है, क्योंकि विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ आवश्यकता, उद्देश्य की सीमा या आनुपातिकता का संदर्भ दिए बिना ही ऐसी शर्तें लागू करते हैं। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है, यदि भविष्य में ऐसी चिंता सामने आती है।

दूसरा, प्रस्तावित नियम 3(4) को जोड़ना है, जो मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, स्पष्टीकरण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में बाध्यकारी बनाता है। नियमों की धारा 79 से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट की जिम्मेदारी के लिए एक सशर्त सुरक्षित ठिकाना मिल गया था, बशर्ते कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें और गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग न लें। बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता-कंटेंट पर नज़र रखने से बचाने के लिए यह मध्यस्थों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में कहा कि सुरक्षित ठिकाना परंपरागत रूप से मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाता रहा है, जब तक कि वे अवैध गतिविधि के वास्तविक ज्ञान पर कार्रवाई करते हैं। इस सिद्धांत ने प्लेटफार्मों को जानकारी के प्रवाह में तटस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेकिन तब से डिजिटल इकोसिस्टम बहुत बदल गया है। प्लेटफार्म अब केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं हैं। उनके आकार और एल्गोरिदम उपयोग करने की उनकी क्षमता ने ऑनलाइन नुकसान और लोगों को प्रभावित करने के तरीकों को बदल दिया है। इस स्थिति में, केवल न्यायालय के आदेश या औपचारिक नोटिस पर प्रतिक्रिया देने वाला मॉडल धीरे-धीरे अप्रभावी हो जाता है। नियम 3(4) शासन को अधिक लचीला बनाकर इस कमी को दूर करता है। यह कंटेंट हटाने के लिए कानूनी आदेशों की आवश्यकता को खत्म नहीं करता; इसके बजाय, यह कार्यकारी उपकरणों के माध्यम से, समग्र रूप से प्लेटफ़ॉर्मों के कार्य करने के तरीके को निर्देशित करने का प्रयास करता है। संभावित अतिशयोक्ति के बारे में वैध चिंताएं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि सुरक्षित ठिकाना शर्तों पर आधारित है, इसका हमेशा मतलब रहा है कि उचित कार्रवाई मानक बदल सकते हैं। चीजों को और अधिक वैध बनाने के लिए, यह समझदारी होगी कि इस प्रकार की सलाहें और एसओपी पारदर्शिता के उपायों के साथ जारी किये जाएँ, जैसे प्रकाशन, अच्छी तरह से सोचा गया कारण, और यदि संभव हो तो, हितधारकों से परामर्श।

तीसरे, संशोधन प्रस्तावित करता है कि नियम 8.1 की उपधारा को इस तरह बदल दिया जाए कि भाग ढ्ढढ्ढ के नियम 14, 15 और 16 न केवल प्रकाशकों पर लागू हों बल्कि मध्यस्थों पर और उपयोगकर्ताओं द्वारा मध्यस्थों के कंप्यूटर संसाधनों पर प्रकाशित समाचार और समसामयिक घटनाक्रम कंटेंट पर भी लागू हों, जो प्रकाशक नहीं हैं। उपयोगकर्ता और प्रकाशक के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। यह डिजिटल मीडिया निरीक्षण फ्रेमवर्क के दायरे में एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जो पहले मुख्य रूप से समाचार और संकलित कंटेंट के संगठित प्रकाशकों के प्रति केंद्रित था। संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं से भी आने वाले कंटेंट के मामले में गंभीर नियम उल्लंघनों को निपटाया जा सके तथा इसके लिए ऐसे कंटेंट को नियम 14 से 16 में शामिल किया गया है। यह पारंपरिक प्रकाशकों और कार्यात्मक रूप से समान गतिविधियों में लगे डिजिटल-स्थानीय कर्मियों के बीच समानता को और बढ़ावा देता है।

इस प्रकार, संशोधन नियामक समानता को बढ़ावा देता है और वर्तमान फ्रेमवर्क में संरचनात्मक कमी को ख़त्म करता है। इसके साथ ही एक विचारशील फीडबैक बिंदु यह है कि भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ का उपयोग उपयोगकर्ता-जनित कंटेंट पर गंभीर और प्रणालीगत नुकसान तक ही सीमित रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू होने से बचने के लिए, जिससे वैध राजनीतिक भाषण या लोगों की खोजी पत्रकारिता पर रोक लग सकती है, मंत्रालय यह विचार कर सकता है कि नियम 14 से 16 के तहत मध्यस्थों को लक्षित हस्तक्षेप; स्पष्ट मानदंडों, जैसे पहुँच, प्रभाव और जोखिम के आधार पर किए जाएंगे तथा न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग किया जाएगा। यह मध्यस्थ द्वारा समर्थन (होस्ट) दिए गये कंटेंट के निरीक्षण को बेहतर बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ-साथ एक खुली और बहुल डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र को बनाए रखने के उद्देश्य के अनुरूप होगा। अंत में, नियम 14 में प्रस्तावित बदलाव, जिसमें शिकायतों को बदलकर मामले किया गया है, एक प्रतिक्रियाशील से अधिक सक्रिय नियामक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।

टिप्पणी

बाल विवाह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की निर्णायक लड़ाई

छत्तीसगढ़ में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल बनती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अभियान को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखते हुए जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बना दिया है। गांव-गांव में जागरूकता और सामाजिक सहभागिता के जरिए बाल विवाह जैसी कुरीति पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। 10 मार्च 2024 से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह रोकना नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, मितानिनें और महिला स्व-सहायता समूह लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अभियान अब प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर सामाजिक चेतना का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। चरणबद्ध योजना के तहत 2025-26 तक 40 प्रतिशत, 2026-27 तक 60 प्रतिशत, 2027-28 तक 80 प्रतिशत और 2028-29 तक सभी ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की तैयारी है। अभियान की प्रगति भी उत्साहजनक रही है।

31 मार्च 2026 तक राज्य की 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में से 7 हजार 498 पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, जो कुल पंचायतों का लगभग 64 प्रतिशत है। वहीं 196 नगरीय निकायों में से 85 निकाय इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं।

राज्य के बालोद जिले ने इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त घोषित कराया है। प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों से मिली यह सफलता अब दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा बन रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां ही होंगी। इसी सोच के साथ सरकार बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है।

कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित होती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। यही कारण है कि अभियान के तहत किशोरियों और अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सके।

पंचायत आधारित जनभागीदारी, सतत निगरानी और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी मॉडल के कारण बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास केवल एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का व्यापक संकल्प बनकर उभर रहा है।

ब्लॉग

बहुपक्षवाद का संकट और डब्लूटीओ में सुधार की अनिवार्यता

राजेश अग्रवाल

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली औचित्य के गहरे संकट का सामना कर रही है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) वैश्विक व्यापार का केंद्रीय स्तंभ था, जो नियम-आधारित व्यवस्था की पेशकश करने के साथ तटस्थता, पूर्वानुमेयता और निष्पक्षता का वादा करता था। हालांकि आज, ये वादे काफी कमजोर प्रतीत होते हैं। डब्लूटीओ में विश्वास की कमी, किसी एक विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक असंतुलन, असमान प्रवर्तन और वैश्विक आर्थिक शक्ति के बदलते स्वरुप के संचयी प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है।

इस संकट के मूल में है - वैश्विक उत्पादन का अत्यधिक केंद्रीकरण और आक्रामक व्यापार प्रथाओं की निरंतरता। समय के साथ, आपूर्ति श्रृंखलाएँ परस्पर अत्यधिक निर्भर हो गई हैं और उनका वितरण भी असमान है, जहाँ कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अनुपात से कई गुनी ज्यादा नियंत्रण रखती हैं। हालांकि, इस केंद्रीकरण ने कुछ मामलों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक कुशल बना दिया है, लेकिन इसने उन्हें काफी हद तक कमजोर भी बना दिया। व्यवधान—चाहे भू-राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या पर्यावरण-संबंधी हों—अब प्रणालीगत नतीजे लेकर आते हैं। परिणामस्वरूप, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी अब केवल एक आर्थिक चिंता के रूप में नहीं देखी जाती; इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक अस्तित्व के मामले के तौर पर देखा जाने लगा है। धारणा में हुए बदलाव ने नीतिगत प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी लहर को जन्म दिया है, जो बहुपक्षवाद के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती देती हैं। देश घरेलू हितों की रक्षा के लिए संरक्षण उपायों, आक्रामक औद्योगिक नीतियों और निर्यात नियंत्रण को अपना रहे हैं। हालांकि ऐसी रणनीतियाँ अल्पकालिक सहनशीलता ला सकती हैं, लेकिन वे डब्लूटीओ की सहयोग भावना और कानूनी रूपरेखा को अक्सर कमजोर कर देती हैं। तकनीकी अवरोध, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण और भू-राजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में बाज़ार पहुंच का बढ़ता उपयोग एक व्यापक परिवर्तन का संकेत देता है: व्यापार अब केवल आर्थिक लेन-देन ही नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति के बारे में है। डब्लूटीओ सदस्यों के बीच एक व्यापक रूप से मान्य दृष्टिकोण यह है कि संगठन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को उनके प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह ठहराने में अक्षम रहा है और इसने वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब नियम असमान रूप से लागू किए जाते हैं या प्रवर्तन तंत्र विफल हो जाते हैं, तो प्रणाली में विश्वास कमजोर हो जाता है। कई देशों में, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में, यह धारणा मजबूत हुई है कि डब्लूटीओ अब एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करता। इसके बजाय, इसे एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाता है, जो तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के प्रति अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा है।

इस संदर्भ में, सुधार प्रयासों का केंद्रीय उद्देश्य डब्लूटीओ की विश्वसनीयता को बहाल करना हो गया है। यद्यपि डब्लूटीओ सुधार की आवश्यकता पर सदस्यों के बीच व्यापक सहमति है, फिर भी इसे हासिल करने के तरीके पर सहमति न के बराबर है। सुधार की संरचना और विषय वस्तु पर बहसें लगातार विवादास्पद होती जा रही हैं। याओंडे के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, सदस्यों ने डब्लूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की, जिनमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, समावेश और सहमति-आधारित निर्णय शामिल हैं। इन सिद्धांतों ने लंबे समय से डब्लूटीओ को अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अलग बनाये रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सदस्य, चाहे उनका आकार या उनकी आर्थिक शक्ति कुछ भी हो, वैश्विक व्यापार नियमों को अंतिम रूप देने में अपनी बात रख सकें। हालांकि, इन सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को, विशेष रूप से बहुपक्षीय समझौतों से जुड़ी चर्चाओं में, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये समझौते डब्लूटीओ सदस्यों के उपसमूहों के बीच बातचीत के बाद तैयार किए गए हैं। इन्हें कई देश—विशेष रूप से वैश्विक उत्तर के देश —सहमति-आधारित नियम निर्माण की चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान मानते हैं। ऐसी सदस्यता के लिए, जहां विकास स्तर और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं, जटिल मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। बहुपक्षीय समझौते आगे बढ़ने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जिससे इच्छुक प्रतिभागी नए नियम स्थापित कर सकते हैं, इसमें उन देशों को रुकावट नहीं माना जाता, जो प्रतिबद्ध होने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, ऐसी ही प्रणाली डब्लूटीओ से पहले गैट, 1947 (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) के तहत अस्तित्व में थी।

इस मुद्दे पर भारत का रुख एक सावधानीपूर्वक तैयार संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है। नियम-निर्माण को आगे बढ़ाने में बहुपक्षीय समझौतों की क्षमता को स्वीकार करते हुए भारत ने लगातार मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि ऐसे समझौतों द्वारा बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर न होना सुनिश्चित हो सके। बहुपक्षीय समझौतों को प्रमुख डब्लूटीओ सिद्धांतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए, मौजूदा कार्यादेश को कमजोर नहीं करना चाहिए या गैर-प्रतिभागी सदस्यों के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुपक्षीय रूपरेखा की जगह लेने के बजाय एक पूरक भूमिका निभानी चाहिए। भारत एक तदर्थ, समझौता-दर-समझौता मॉडल के बजाय बहुपक्षीय समझौतों को डब्लूटीओ संरचना में समेकित करने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सुधार बहस का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, संगठन के पिछले कार्यादेशों को पूरा करने में विफलता से संबंधित है। यह कई विकासशील देशों के लिए असंतोष का एक प्रमुख कारण रहा है। ये अधूरी प्रतिबद्धताएं—जिनमें कृषि, विकास और विशेष व्यवहार प्रावधानों जैसे क्षेत्र शामिल हैं — केवल नियम बनाने की कमियों को ही नहीं दर्शातीं, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में लंबे समय से मौजूद असमानताओं को दूर करने के अवसरों की चूक को भी उजागर करती हैं। विशेष रूप से कृषि, इन असंतुलनों की गंभीरता को दर्शाती है। विकसित देशों ने अपने कृषि क्षेत्रों को सब्सिडी देने में महत्वपूर्ण लचीलापन बनाए रखा है, जिससे उनके किसान वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। वहीं, विकासशील देशों को अपने किसानों को दिए जाने वाले समर्थन के प्रकारों और स्तरों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। यह विषमता संरचनात्मक असुविधाओं को बनाए रखती है, वैश्विक दक्षिण में लाखों लोगों की आजीविका को कमजोर करती है और वैश्विक व्यापार प्रवाह को विकृत करती है। कृषि से परे, ऐसी न्यायसंगत रूपरेखाओं की मांग बढ़ रही है, जो प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और क्षमता निर्माण को नियंत्रित करती हैं। तेज़ तकनीकी प्रगति के युग में ज्ञान, नवाचार और ज्ञान-कौशल तक पहुँच आर्थिक विकास का एक प्रमुख निर्धारक बन गया है। फिर भी, मौजूदा नियम अक्सर मौजूदा पदानुक्रम को मजबूत करते हैं, जिससे विकासशील देशों की मूल्य श्रृंखला में ऊपरी पायदान पर चढ़ने की क्षमता सीमित हो जाती है। अधिक समावेशी और संतुलित व्यापार प्रणाली बनाने के लिए इन असमताओं को दूर करना आवश्यक है।

विशेष और विभेदपूर्ण व्यवहार (एस एंड डीटी) पर बहस डब्लूटीओ सुधार की जटिलताओं को और अधिक उजागर करती है। एस एंड डीटी मूल रूप से सबसे कम विकसित और विकासशील देशों को गैर-पारस्परिक बाजार पहुँच और व्यापार प्रतिबद्धताओं को लागू करने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अब एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। कुछ विकसित देशों का तर्क है कि स्व-निर्धारण की मौजूदा प्रणाली अपेक्षाकृत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को उन प्रावधानों से लगातार लाभ उठाने की अनुमति देती है, जो कम विकसित राष्ट्रों के लिए बनाए गए थे। भारत इन चिंताओं को स्वीकार करता है, लेकिन सकल आर्थिक आकार जैसे मनमाने पैमानों पर आधारित सरल समाधानों के प्रति आगाह भी करता है। इसके बजाय, ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि एस एंड डीटी वास्तविक विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण बना रहे। इसके लिए एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है—ऐसा दृष्टिकोण, जो विकासशील दुनिया में मौजूद आर्थिक स्थितियों की विविधता को मान्यता देता हो और उसी के अनुसार लचीलापन तैयार करता हो। यह मुद्दा और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि कई विकसित देशों ने कृषि सब्सिडी अधिकारों के संदर्भ में, जिसे कभी-कभी विपरीत एस एंड डीटी कहा जाता है, का फायदा उठाना जारी रखा है।

अंततः, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का भविष्य इसके सदस्यों की प्रतिस्पर्धी हितों को सुलझाने और साझा संस्थानों में विश्वास पुनः स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। चुनौतियाँ कठिन हैं, लेकिन हित इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। एक कमजोर डब्लूटीओ से एक विभाजित वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म देने का खतरा है, जो एकपक्षीय और शक्ति-आधारित सौदेबाज़ी पर आधारित हो सकती है। इसके विपरीत, सुधार किये गये और फिर से सशक्त बनाये गये डब्लूटीओ में एक अधिक सुदृढ़, समावेशी और सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था को आधार प्रदान करने की क्षमता है। भारत की व्यापक व्यापार रणनीति, बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों के साथ जोड़ती है। जैसे-जैसे व्यापार नीति जटिल होती जा रही है—जिसमें नियामक मानक, डिजिटल शासन और आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण शामिल है—समान विचारधारा वाले भागीदारों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मजबूत आर्थिक एकीकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरे हैं। हालांकि, वर्तमान में जारी चर्चाओं में भारत की रचनात्मक भागीदारी इस कार्य की तात्कालिकता और जटिलता, दोनों को प्रतिबिंबित करती है। संतुलित, समावेशी और भविष्य-केंद्रित सुधारों को समर्थन देकर, भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि डब्लूटीओ तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बना रहे—एक ऐसा संस्थान, जो न केवल व्यापार को प्रबंधित करने में सक्षम हो, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक भविष्य को आकार देने की भी क्षमता रखता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्लूटीओ व्यवसायों को निश्चितता, पूर्वानुमेयता, समावेशिता, समानता और सरलता प्रदान करता है, यानि नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था।

गोरखपुर फोरलेन पर डीसीएम ने मजदूरों को रौंदा, एक की मौत और चार घायल

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। वाराणसी फोरलेन पर मिक्सर मशीन का पंचर टायर बदल रहे मजदूरों को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक और उसके सहयोगी को पकड़कर गगहा थाना पुलिस के हवाले कर दिया।

गगहा क्षेत्र के सिहाइजपार निवासी सद्दाम शाही सटरिंग का काम करते हैं। शनिवार को उनके साथ करीब एक दर्जन मजदूर मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर पर सवार होकर छत ढलाई के काम के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फोरलेन पर शिवपुर गांव के सामने पहुंचते ही मिक्सर मशीन का टायर पंचर हो

गया। इसके बाद मजदूर सड़क किनारे वाहन रोककर टायर बदलने लगे। सूचना मिलने पर कारोबारी सद्दाम शाही भी बाइक से मौके पर पहुंच गए। मजदूर मिक्सर मशीन के पीछे खड़े होकर टायर खोल रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि मिक्सर मशीन के पास खड़े मजदूर दूर जा गिरे। हादसे में 35 वर्षीय अनिल यादव पुत्र वैजनाथ निवासी सिहाइजपार की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अज्जू, विकास, रामदयाल और सद्दाम शाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद अज्जू और विकास की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

दुर्घटना के बाद भागने का प्रयास कर रहे डीसीएम चालक और उसके सहयोगी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और गगहा पुलिस को सौंप दिया। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाइवे से हटा लिया गया है।

यूपी पंचायत चुनाव : प्रधानी खत्म होने के बाद भी 'पावर' में रहेंगे ग्राम प्रधान, मंत्री राजभर ने दिया बड़ा संकेत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने की दशा में विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया।

पंचायती राज विभाग का विचार है कि ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रशासक नियुक्त किया जाए। वैसे इस पर मुख्यमंत्री जो भी उचित होगा एक दो दिन में इस पर निर्णय लेंगे।

शुक्रवार की शाम मरदह क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री ओपी राजभर ने पत्रकार वार्ता में मऊ विधायक अब्बास अंसारी के बारे में सवाल के जवाब में कहा कि वह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो सुभासपा के सिंबल पर जीते हैं। अब्बास अंसारी को पुनः सुभासपा से चुनाव लड़ाने के सवाल पर बोले कि कतई टिकट नहीं देंगे। बकौल मंत्री, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि मैंने अपना नेता उन्हें चुनाव

लड़ने के लिए दिया था।

सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथार्टी है। पी से परिवार, डी से डिंपल व ए से अखिलेश यादव हैं। कहा कि जब अखिलेश यादव पांच साल मुख्यमंत्री थे, तब पीडीए की याद नहीं आई।

कहा कि सपा सरकार में शिवपाल यादव सरकारी नौकरियों में भर्ती की सूची बनाते थे और अखिलेश यादव उस पर हस्ताक्षर करते थे। समाजवादी पार्टी में यही लोग लूटते थे । कहा कि सपा सरकार में अनिल यादव को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाने पर हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई थी।

अलीगढ़ में 24 मई को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा : 4467 अभ्यर्थी 11 केंद्रों पर देंगे एग्जाम

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को जिले में दो पालियों में कराई जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। शहर में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 4467 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

डीएम ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हीट वेव को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, पंखे, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाएं समय से दुरुस्त रखने को कहा।

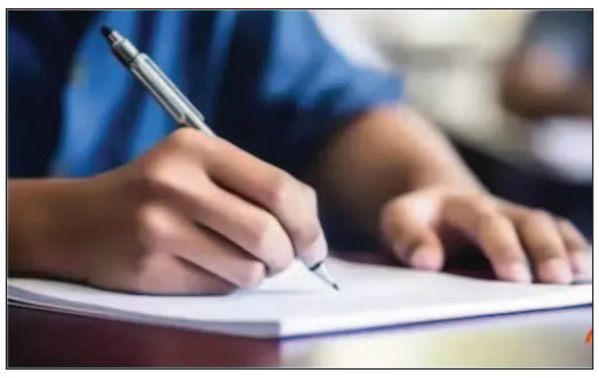

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

सभी केंद्रों पर लगाए जाएंगे जैमर व अन्य व्यवस्था होंगी उपलब्ध

अधिकारियों को पॉवर प्वाइंट व विद्युत व्यवस्थाओं की पहले से जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, चंपा अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, धर्म समाज महाविद्यालय, डीएवी इंटर कॉलेज, रतन प्रेम डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज, एसएमबी इंटर कॉलेज, श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज व श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

ताइक्वांडो में कुशाग्र राव ने जीता गोल्ड मेडल, जिले का बढ़ाया मान

सुलतानपुर। होनहार खिलाड़ी कुशाग्र राव ने सीआईएससीई ज़ोनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2026 की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 वर्ग (35-38 किलोग्राम) में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 20 मई तक लखनऊ पब्लिक कॉलेज, राजाजीपुरम में हुआ था।

अमीना ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ी कुशाग्र राव को इस उपलब्धि पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने खिलाड़ी की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि युवा प्रतिभाएं जिले का गौरव हैं। इस दौरान प्रशिक्षिका अमीना बानो के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी सराहना की गई। अकादमी पदाधिकारियों ने कुशाग्र राव और उनके परिजनों को बधाई देते हुए भविष्य में और बड़ी सफलताओं की कामना की।

'फ्री फायर गेम की आईडी देंगे...' पिता के खातों से बेटे ने 3 साइबर ठगों को लाखों ट्रांसफर किए

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर जिले में ऑनलाइन गेमिंग की लत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फ्री फायर गेम की आईडी और इन-गेम सुविधाएं पाने के लालच में एक 11वीं के छात्र ने अपने ही पिता के बैंक खाते से करीब 2.96 लाख रुपये साइबर ठगों को ट्रांसफर कर दिए। घटना की जानकारी होने पर पिता ने साइबर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार छात्र लंबे समय से फ्री फायर गेम खेल रहा था और इस दौरान वह सोशल मीडिया व मोबाइल कॉल के जरिए कुछ लोगों के संपर्क में आया। ठगों ने उसे प्रीमियम गेम आईडी, खास फीचर्स और गेमिंग रिवॉर्ड दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद छात्र ने चोरी-छिपे अपने पिता के बैंक खाते से कई बार में पैसे ठगों के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर करने

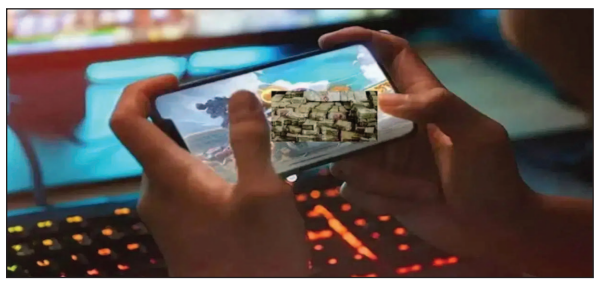

शुरू कर दिए। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी।

पिता को कैसे चला पता?

मामला तब खुला जब बैंक खाते से लगातार रकम कटने पर पिता को शक हुआ। जांच करने पर सामने आया कि बेटे ने ऑनलाइन ऐप के जरिए अलग-अलग खातों में पैसे भेजे थे। पीड़ित परिवार ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन खातों और मोबाइल नंबरों की पड़ताल कर रही है, जिनके पैसे भेजे गए हैं। साइबर थाना प्रभारी राशीद खान ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है।

ठगों ने कैसे बनाया बच्चे को निशाना?

पीड़ित छात्र के मुताबिक, 7 मार्च को उसके पास पुष्पेंद्र सिंह नाम के युवक का फोन आया। उसने खुद को गेमिंग एक्सपर्ट बताते हुए फ्री फायर की खास आईडी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले उसने पैसे मांगे। गेमिंग के जुनून में छात्र ने अपने पिता के खाते से गूगल पे के जरिए करीब 1.55 लाख रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए। कुछ दिनों बाद छात्र की पहचान कुनाल नाम के एक अन्य युवक से हुई। उसने भी प्रीमियम गेम आईडी और खास फीचर्स दिलाने का दावा किया। छात्र उसके झांसे में आ गया और करीब 85 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठग ने भरोसा जीतने के लिए एक गेम आईडी भी भेजी, जो फिलहाल छात्र के पास मौजूद बताई जा रही है।

मामला यहीं नहीं रुका। 23 अप्रैल को छात्र की बातचीत विनीत कुमार मिश्रा नाम के युवक से हुई। उसने भी गेम आईडी अपग्रेड और एक्सेस दिलाने के नाम पर 56 हजार रुपये की मांग कर दी। छात्र ने बताए गए बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। इस तरह अलग-अलग लोगों ने मिलकर छात्र से कुल 2.96 लाख रुपये ठग लिए।

नहीं थी बिजली, तो घर के बाहर सो रहा था परिवार... तेज रफ्तार डंपर ने कुचला, बाराबंकी में पिता और 3 बच्चों की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी जिले में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी और बिजली कटौती के कारण घर के बाहर सो रहे एक परिवार पर तेज रफ्तार डंपर मौत बनकर टूट पड़ा। हादसे में पिता और उसके तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

हादसा फतेहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर-महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसा गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि गांव निवासी 35 वर्षीय नीरज अपने परिवार के साथ घर के बाहर सो रहा था। इलाके में लंबे समय से बिजली नहीं आने के कारण परिवार खुले में सोने को मजबूर था। देर रात अचानक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित

होकर सड़क किनारे पहुंच गया। पहले उसने एक पेड़ को जोरदार टक्कर मारी और फिर सीधे सो रहे परिवार पर चढ़ गया।

मौके पर ही 2 की हो गई मौत

हादसा इतना भयावह था कि नीरज और उसके 13 वर्षीय बेटे अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 10 वर्षीय अंशिका और 6 वर्षीय आंशू को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में नीरज की पत्नी 35 वर्षीय आरती गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

ड्राइवर का काम करता था नीरज

स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक नीरज किराये पर मैजिक वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और गर्मी के कारण रोज की तरह घर के बाहर ही सोया हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात उनके लिए आखिरी साबित होगी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिजली व्यवस्था ठीक होती तो शायद यह परिवार आज जिंदा होता।

शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन ने शहीदों के नाम पर किया रक्तदान

सुलतानपुर। शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जिला अस्पताल में शनिवार को शहीदों के नाम पर कैंप लगा कर रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सीएमएस डॉ अभिनाश गुप्ता और सी एम एस संजय सिंह और डॉ अनुराग पाण्डेय और डॉ विजय चौधरी ने किया। किसी जरूरमंद को खून देने पर जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बया नहीं किया जा सकता किसी तरह हमारा रक्त किसी की जिंदगी बचाने में हमे बहुत खुशी मिलती है खून के अभाव में न जाने कितने लोग दम तोड़ देते है संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अलमदार हुसैन ने बताया शियाने हैदर ए कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 23 मई को शहीदों की याद में 26 यूनिट खून दिया गया। इस मौके पर संस्था के नौवजवान मौजूद रहे डॉ मोहताशम, मोहम्मद मेंहदी, गुलाम हैदर, बाकर, अलमदार हुसैन आदि मौजूद रहे।

सिलेंडर फटने से लगी आग, लाखों की गृहस्थी जलकर राख

आर्यावर्त संवाददाता

मीरजापुर। जिले के हलिया थाना क्षेत्र के चक कोटार गांव में शुक्रवार की देर रात सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक ही परिवार की चार गृहस्थियों का लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार चक कोटार गांव निवासी कैलाश मौर्य के घर के पीछे बने किचन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गृहस्वामी द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड व पीआरबी 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से काफी प्रयास के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था। गृहस्वामी कैलाश मौर्य ने बताया कि आग में करीब 15 बोरी सरसों, 20 बोरी गेहूं, 16 बोरी चावल, तीन बोरी अरहर दाल, एक कुंतल चना, 10 किलो हल्दी, एक कुंतल प्याज, एक कुंतल लहसुन, एक कुंतल गुड़, दो गैस सिलेंडर, 20 कुंतल सूखा चारा समेत गृहस्थी का पूरा सामान, कूकर व बर्तन आदि जलकर राख हो गए।

बताया गया कि कैलाश मौर्य के चारों बेटे अलग-अलग गृहस्थी बनाकर उसी मकान में रहते थे। आग लगने से सभी की गृहस्थी पूरी तरह नष्ट हो गई। घटना की सूचना लेखपाल को दे दी गई है। वहीं ग्राम प्रधान असानी ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

धर्म की रक्षा के लिए भगवान लेते हैं अवतार : प्रशांत कुमार मिश्रा

आर्यावर्त संवाददाता

लालगंज, मीरजापुर। बल्हिया खुर्द गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में शनिवार को भगवान वराह अवतार, सृष्टि वर्णन और सुकागमन प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। वृंदावन धाम के कथावाचक महाराज प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कथावाचक ने सुकदेव जी के आगमन प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि संतों का जीवन समाज को सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए होता है। संत समाज में प्रेम, त्याग और सदाचार की भावना जागृत करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जिससे जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है। सृष्टि वर्णन प्रसंग में महाराज ने कहा कि ईश्वर ने संपूर्ण संसार की रचना जीवों के कल्याण के लिए की है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है।इसलिए जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का माध्यम भी है।भगवान वराह अवतार की कथा सुनाते हुए महाराज ने बताया कि दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में पहुंचा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और अधर्म का अंत किया। भगवान का यहे अवतार धर्म, सत्य और मानव कल्याण का प्रतीक माना जाता है।कथा के उपरांत भजन-कीर्तन और आरती पूजन हुआ। आयोजन समिति के हरिशंकर मिश्रा, मालती मिश्रा एवं रमाशंकर मिश्रा ने विधि-विधान से आरती की। कथा स्थल पर श्रद्धालु देर शाम तक कथा श्रवण करते रहे।

मां ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, 10 साल के बेटे ने बनाया वीडियो

आर्यावर्त संवाददाता

जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई से दिल चीरने वाली खबर सामने आई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार में कलह इस कदर हावी हुई की एक मां ने आवेश में आकर ममता का गला घोंट दिया। बृहस्पतिवार रात दंपती के बीच नोकझोंक के बाद मां ने चार साल की बेटी की गमछे से गला कसकर हत्या कर दी। इस वारदात को दस साल के बेटे ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

आटा क्षेत्र के अकबरपुर इटौरा निवासी राजकुमार रात दोनों बेटों उमंग (10) और मयंक के साथ लेटे थे। पत्नी विनीता दूसरी चारपाई पर बेटी नैना (4) के संग लेटी थी। पति का आरोप है कि पत्नी दो दिन से मायके जाने की जिद कर रही थी।

उसने पैसे ने होने का हवाला दिया था। रात में जब सब सो गए तभी विनीता ने बेटी को मार दिया। बिजली जाने पर नींद खुली तो देखा बेटी जमीन पर पड़ी है और विनीता बैठी थी और मासूम बच्ची का गला कस रही थी। इसी दौरान बेटे उमंग ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि हुई है।

या तू रहेगा या मैं, पति बोला- मुझे फंसाने की थी तैयारी

आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर इटौरा गांव में घरेलू कलह में चार वर्षीय मासूम बेटी की हत्या के मामले में पति राजकुमार ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी पत्नी का व्यवहार काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है और सीमित आमदनी के कारण पत्नी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। राजकुमार ने बताया कि बुधवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि उसी दौरान विनीता ने कहा था कि "या तू रहेगा या मैं। राजकुमार का कहना है कि अगर वह समय रहते जाग नहीं जाता तो संभव है कि उसे ही इस मामले में फंसा दिया जाता। घटना के बाद से परिवार पूरी तरह टूट गया है और गांव में दहशत व शोक का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक विनीता ने गमछे का टुकड़ा फाड़कर बच्ची के गले में बांधा और उसे कस दिया। घटना को लेकर गांव में गहरा आक्रोश और दुख का माहौल है।

लोग कह रहे हैं कि जिस मां की गोद में बच्ची खुद को सबसे सुरक्षित समझती थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। बताया गया कि घटना से पहले विनीता ने जमीन पर लाल साड़ी बिछाई थी। इसके बाद वह नैना को गोद में उठाकर वहां ले गई। घटना के बाद बच्ची का शव उसी साड़ी पर पड़ा मिला।

यह दृश्य देखकर गांव की महिलाओं की आंखें नम हो गईं। घर में तीन चारपाइयां बिछी थीं। एक पर राजकुमार अपने दोनों बेटों के साथ सो रहे थे, जबकि दूसरी पर विनीता और नैना थीं। तीसरी चारपाई खाली पड़ी थी। रात में बच्ची की जान चली गई और पास में सो रहे पिता व भाइयों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

'बिट्टो' कहकर बुलाते थे मोहल्ले वाले

चार साल की नैना को परिवार और मोहल्ले के लोग प्यार से 'बिट्टो' कहकर बुलाते थे। वह चंचल स्वभाव की थी और सभी की दुलारी थी। सुबह जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। लोग यही कहते नजर आए कि अब उनकी 'बिट्टो' कभी लौटकर नहीं आएगी।

सजने-संवरने की शौकीन थी नैना

परिजनों ने बताया कि नैना को सजने-संवरने का बेहद शौक था। वह हाथों में बड़ी-बड़ी चूड़ियां पहनकर मोहल्ले में घूमती थी। उसकी मासूम हरकतें सभी को पसंद थीं। उसकी मौत के बाद मोहल्ले की रौनक जैसे खत्म हो गई है।

डर के साए में कटी विनीता की रात

चार साल की मासूम नैना की हत्या के बाद मां विनीता और उसका परिवार पूरी रात डर और सदमे में डूबा रहा। बताया गया कि बृहस्पतिवार रात करीब 12 बजे विनीता ने बेटी का गला घोंट दिया। कुछ देर बाद पास में सो रहे पति राजकुमार और दोनों भाइयों को घटना की जानकारी हुई।

रात अधिक होने के कारण परिवार पूरी रात शव के पास बैठा रहा और सुबह होते ही मोहल्ले व रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी गई। सुबह पुलिस ने हत्यारोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घर बनेगा खूबसूरत, सेहत को भी होगा फायदा...इन चीजों से करें सजावट

घर को डेकोरेट करना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर दिखे। सोचिए कि अगर यही सजावट आपकी सेहत को दुरुस्त रखें तो कैसा रहेगा। ऐसे ही कुछ डेकोरेशन आइडिया हैं जो आपके घर को खूबसूरत दिखाएंगे साथ ही इससे आपकी सेहत को भी फायदा होगा।

"एक पंथ दो काज" ये कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी। इसका मतलब होता है कि एक ही चीज से दो फायदे हो जाना। ऐसे ही डेकोरेशन आइडिया हम आपको देने जा रहे हैं। इससे आपके अपने घर को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई आने-जाने वाला तारीफ करते नहीं थकेगा। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि घर की सजावट आपकी सेहत को भी फायदा पहुंचाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर को बेहद सुंदर और एंटीक भी दिखाती हैं साथ ही आपको रिलैक्स फील होगा। इससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फायदा भी पहुंचेगा।

एयर प्यूरीफाइंग इंडोर प्लांट

घर में हरियाली मन को सुकून पहुंचाती है और इससे घर देखने में भी अच्छा लगता है। बालकनी में तो ज्यादातर लोग पौधे लगाते ही हैं। इसके अलावा इंडोर प्लांट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। बस आप ऐसे प्लांट लगाएं जो नेचुरल एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। इन प्लांट को आप लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट (Snake Plant),स्पाइडर प्लांट (Spider Plant), एरिका पाम (Areca Palm), पीस लिली (Peace Lily), लगा सकते हैं। इससे घर ठंडा भी रहेगा और हवा भी शुद्ध रहेगी जो हेल्दी रहने के लिए बहुत आवश्यक है।

हर्ब कॉर्नर बनाएं

अपने घर के एक कोने में या फिर किचन की विंडो के पास आप हर्बल कॉर्नर बना सकते हैं। इसमें आप तुलसी, पुदीना, एलोवेरा, धनिया, लेमन ग्रास, रोजमेरी, करी पत्ता, उगा सकते हैं। ये सारी हर्ब आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा सेहत को भी फायदा पहुंचता है। आपके ये कॉर्नर सिर्फ घर की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हेल्थ भी दुरुस्त रहेगी।

हिमालयन साल्ट लैंप

आप अपने घर में हिमालयन साल्ट लैंप रख सकते हैं। यह लैंप देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है और आपके घर को क्लासी लुक देता है। ये लैंप ये हवा से धूल, बारीक अशुद्धी वाले कणों, पालतू जानवरों की रूसी आदि को खींचकर हवा को शुद्ध करने का काम करती है। इसलिए एलर्जी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम वालों के लिए फायदेमंद रहती है। इसके अलावा इसकी हल्की रोशनी से आंखों को सुकून पहुंचता है। बेडरूम में इसे लगा सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स नींद लाने में भी हेल्प मिल सकती है।

एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर

आप अपने घर की सजावट के आइटम्स में एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर को शामिल कर सकते हैं। ये देखने में काफी क्लासी लगते हैं और आपके घर को एंटीक टच देने में मदद करते हैं। मार्केट में एक से बढ़कर एक डिजाइन के डिफ्यूजर मिल जाएंगे। इसे आप मनपसंद खुशबू के ऑयल के साथ घर में रखकर चालू कर दें। इससे निकलने वाली धीमी-धीमी खुशबू रिलैक्स महसूस कराती है, जिससे स्ट्रेस दूर होता है। आप इसमें लैवेंडर, यूकेलिप्टस जैसे एशेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं जो मूड को बूस्ट भी करते हैं और नींद को भी बेहतर कर सकते हैं।

इको-फ्रेंडली फर्नीचर-पर्दे

घर की सजावट में ऐसे फर्नीचर और पर्दे, चादर का इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हो। जैसे आप फर्नीचर के लिए केमिकल फ्री नेचुरल लकड़ी का यूज करें। इसके अलावा दीवारों के लिए ऐसे रंग चुनें जिसमें 'VOC' (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) की मात्रा बहुत कम हो या फिर ये 'VOC' फ्री हो। गहरे रंग के कॉर्टेन्स की बजाय लाइट कलर के पर्दे लगाएं जो देखने में अच्छे लगेंगे और मन को भी सुकून पहुंचाएंगे। इसी तरह से कुशन कवर, बेड शीट के लिए कॉटन, लिनन, जैसे कपड़ों का यूज करें। सिंथेटिक फैब्रिक से बचें।

गर्मियों में कितने दिन में बदलनी चाहिए गमले की मिट्टी, ध्यान रखें ये जरूरी बातें

गर्मियों के मौसम में पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। गर्म हवाएं, तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी की वजह से पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में गमले की मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाती है, जिसका सीधा असर पौधे की हेल्थ पर पड़ता है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और जड़ें भी सूख जाती हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अगर आपको अपने पौधे के हरा-भार रखना है तो उसकी पानी और खाद देने के अलावा गमले की मिट्टी बदलना भी जरूरी होता है।

हालांकि बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि मिट्टी कितने दिन में बदलनी चाहिए और इसे बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सही समय पर मिट्टी बदलने से पौधों को जरूरी पोषण मिलता है, जड़ों को पर्याप्त हवा मिलती है और पौधे लंबे समय तक हरे-भरे बने रहते हैं। चलिए इस आर्टिकल में आपको भी बताते हैं गमले की मिट्टी बदलने का सही समय क्या है?

कितने दिन में बदलनी चाहिए गमले की मिट्टी?

अगर आपको अपने पौधे को हेल्दी रखना है तो गमले की मिट्टी को समय-समय पर बदलना बेहद जरूरी है। क्योंकि वक्त के साथ मिट्टी के पोषक तत्व कम होने लगते हैं। ऐसे में मिट्टी बदला पौधे की सेहत के लिए अच्छा होता है। आमतौर पर छोटे गमलों की मिट्टी 8 से 12 महीने में और बड़े गमलों की मिट्टी 1 से 2 साल में बदल देनी चाहिए। अगर यदि मिट्टी बहुत सख्त हो जाए, पानी ऊपर ही रुकने लगे या पौधा कमजोर दिखे, तो मिट्टी जल्दी बदलना बेहतर रहता है। बरसात शुरू होने से पहले या बसंत के मौसम में मिट्टी बदलना सबसे अच्छा माना जाता है।

नई मिट्टी ऐसे करें तैयार?

नई मिट्टी तैयार करते समय केवल साधारण मिट्टी का उपयोग न करें। अच्छी ग्रोथ के लिए 50% गार्डन मिट्टी, 30% गोबर की सड़ी खाद या कम्पोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट मिलाना अच्छा रहता है। इसमें थोड़ी नीम खली, बोनमील या वर्मीकम्पोस्ट डालने से पौधों को एक्स्ट्रा पोषण मिलता है और जड़ों में सड़न कम होती है। ध्यान रहे कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी और पानी निकालने वाली होनी चाहिए।

इन बातों का रखें खास ध्यान

पौधे को जिंदा और हरा-भरा रखने के लिए उसकी केयर करना भी जरूरी है। जैसे समय-समय पर प्लांट की पीली हुई पत्तियों को काटें। इससे नई शाखाएं और नई पत्तियां तेजी से निकलती हैं। फूल वाले पौधों में सूखे फूल भी हटाते रहें ताकि पौधे की ऊर्जा नई कलियों में लगे। बहुत ज्यादा छंटाई गर्मियों की तेज धूप या कड़ाके की सर्दी में नहीं करनी चाहिए।

गर्मी में जिम रूटीन फॉलो करते हैं तो नहीं करें ये गलतियां, हार्ट अटैक का खतरा

आजकल लोग फिट रहने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा जिम करना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में... क्योंकि इस मौसम में शरीर पहले ही डिहाइड्रेशन, थकावट और बढ़ते तापमान से जूझ रहा होता है। ऐसे में अगर सही तरीके से जिम रूटीन फॉलो न किया जाए तो इससे हार्ट पर बुरा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट भी बताते हैं कि, गर्मियों में हार्ट अटैक, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आने और अचानक बेहोशी जैसी समस्याओं के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं, खासकर उन लोगों में जो भारी वर्कआउट करते हैं।

अगर आप भी जिम जाते हैं और वर्कआउट करने के दौरान या बाद में सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि गर्मी में जिम जाने वाले लोगों को किन गलतियों से बचना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक का खतरा न बढ़ें।

जरूरत से ज्यादा कार्डियो करना

गर्मियों में लंबे समय तक ट्रेडमिल, रनिंग या हाई-इंटेंसिटी कार्डियो करने से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ सकती है। लगातार ओवरवर्कआउट करने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से बीपी या दिल से जुड़ी समस्या हो।

पानी कम पीना

एनसीबीआई के मुताबिक, गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है। अगर वर्कआउट के दौरान पर्याप्त पानी न पिया जाए, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है।

खाली पेट एक्सरसाइज करना

कई लोग तेजी से वजन कम करने के लिए खाली पेट जिम चले जाते हैं। बिना कुछ खाए भारी वर्कआउट करने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, जिससे चक्कर, कमजोरी और लो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। इससे हार्ट की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

वार्मअप छोड़ देना

सीधे भारी वेट उठाना या तेज एक्सरसाइज शुरू करना दिल और मांसपेशियों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वार्मअप न करने से शरीर अचानक स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे हार्ट बीट तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए वर्कआउट से पहले कम से कम 10 मिनट का वार्मअप जरूरी माना जाता है।

जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट लेना

कुछ लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन, प्री-वर्कआउट ड्रिंक या अन्य सप्लीमेंट्स का जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं। कई सप्लीमेंट्स में कैफीन और स्टिमुलेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं, जो दिल की धड़कन बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में इसका असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है।

गर्मियों के लिए परफेक्ट हैं ये 5 फेस मिस्ट

गर्मी के कारण त्वचा पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में त्वचा को ठंडक देने के लिए आप बाजार से फेस मिस्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उनमें मौजूद अप्राकृतिक रंग और खुशबू त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस मिस्ट बनाने का तरीका बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे आपकी त्वचा को ठंडक और नमी मिलेगी।

खीरे का फेस मिस्ट

खीरे का फेस मिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में खीरे को अच्छे से पीसें, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें। जब भी आपको लगे कि गर्मी से आपकी त्वचा काफी बेजान हो गई है, तो उस पर खीरे के फेस मिस्ट का छिड़काव करें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ उसे ठंडक भी देगा। खीरे के इस फेस मिस्ट से आपकी त्वचा को ताजगी मिलेगी।

गुलाब जल और नींबू का फेस मिस्ट

गुलाब जल और नींबू का फेस मिस्ट न केवल त्वचा को ताजगी देता है, बल्कि इसे नमी भी देता है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे गुलाब जल के साथ नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को ठंडक देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। गुलाब जल और नींबू का यह मिस्ट आपकी त्वचा को तरोताजा बनाए रखेगा।

एलोवेरा और खीरे का फेस मिस्ट

एलोवेरा और खीरे का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे नमी भी देता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे एलोवेरा जेल के साथ खीरे का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट त्वचा को पोषण देने के साथ इसे ताजगी भरा भी महसूस कराएगा। एलोवेरा और खीरे का यह मिस्ट आपकी त्वचा को नमी देगा।

पुदीना और नारियल पानी का फेस मिस्ट

पुदीना और नारियल पानी का फेस मिस्ट गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें मौजूद पुदीने की ताजगी और नारियल पानी की ठंडक आपकी त्वचा को तरोताजा रखती है। इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में ताजे पुदीने के पत्ते डालें, फिर उसमें नारियल पानी डालकर अच्छे से हिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर छिड़कें। यह फेस मिस्ट आपकी त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे नमी भी देगा।

गुड़हल फूल का फेस मिस्ट

गुड़हल फूल का फेस मिस्ट आपकी त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल फूल की पंखुड़ियों को पानी में उबालें, फिर इस मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इसे अपने चेहरे पर छिड़कें। इन फेस मिस्ट के इस्तेमाल से आप गर्मियों में तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी त्वचा भी खिली-खिली रहेगी।

मुंबई की बारिश पर लगेगा पैसा! भारत में पहली बार होगी बरसात पर ट्रेडिंग

भारत के प्रमुख कृषि कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX ने देश का पहला वेदर डेरिवेटिव पेश किया है। इसके तहत शुरुआत में मुंबई की मानसूनी बारिश के आंकड़ों के आधार पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग की जाएगी। मुंबई के मौसम विभाग के आधिकारिक बारिश के आंकड़ों (मिमी में) को बेंचमार्क मानकर इन कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट किया जाएगा।

एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम "RAINMUMBAI" है। यह कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में बारिश के डेटा पर बेस्ड है। यह डेटा भारत मौसम विज्ञान विभाग से लिया जाएगा। NCDEX के MD और CEO, अरुण रास्ते ने कहा कि भारत सदियों से मॉनसून की अनिश्चितता के साथ जीता आया है। RAINMUMBAI हर स्टेकहोल्डर को इस अनिश्चितता को मैनेज करने के लिए एक रेगुलेटेड, साइंटिफिक टूल देगा।

कैसे काम करेगा मार्केट?

एक्सचेंज के अनुसार, यह कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में हिस्सा लेने वालों को बारिश में उतार-चढ़ाव से होने वाले फाइनेंशियल जोखिमों से बचने (हेज करने) में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट कैश-सेटल होगा और मानसून के मौसम के दौरान शहर के लॉन्ग-पीरियड एवरेज (LPA) से असल बारिश के अंतर को ट्रैक करेगा। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के कॉन्ट्रैक्ट ही उपलब्ध होंगे, जो मुंबई के मानसून पैटर्न को ट्रैक करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइंटिफिक तरीके से बनाए गए 'क्युमुलेटिव डेविएशन रेनफॉल' (CDR) मॉडल पर आधारित हैं।

यह मानसून के महीनों (जून से सितंबर) के दौरान लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) से असल बारिश के अंतर को मापता है। यह मॉडल और प्रोडक्ट IIT बॉम्बे के साथ मिलकर बनाया गया था। हालांकि, NCDEX ने लिक्विडिटी से जुड़ी चिंताओं को भी माना है, और एक 'मार्केट मेकर' नियुक्त किया है ताकि यह पक्का हो सके कि ट्रेडर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड बने रहें।

वेदर डेरिवेटिव क्या है?

वेदर डेरिवेटिव ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स को मौसम की अनप्रेडिक्टेबल स्थितियों, जैसे तापमान, बर्फबारी या लू से होने वाले जोखिमों से बचने (हेज करने) की सुविधा देते हैं। NCDEX का RAINMUMBAI अपनी तरह का पहला बारिश पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है। इसे इंश्योरेंस के एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां इंश्योरेंस किसी फिजिकल नुकसान या हानि के बाद पेमेंट करता है, वहीं वेदर डेरिवेटिव पहले से तय मौसम के डेटा के आधार पर पेमेंट करते हैं। इस मामले में, अगर मुंबई में बारिश ऐतिहासिक एवरेज से अलग होती है, तो पेमेंट किया जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दुनिया भर में एग्रीकल्चर, पावर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जहां मौसम में होने वाले बदलावों का रेवेन्यू पर काफी असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कोई पावर कंपनी असामान्य रूप से ठंडे मानसून के दौरान बिजली की कम मांग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बारिश से जुड़े डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कोई एग्रीकल्चरल लेंडर (कर्ज़ देने वाला) कम बारिश के कारण एग्रीकल्चरल पैदावार में आई कमी से खुद को सुरक्षित रख सकता है।

देश में आ रही गन्ने और मक्के से चलने वाली गाड़ियां, लेकिन ऑटो कंपनियों ने सरकार के सामने रख दी ये बड़ी शर्त

बहुत जल्द देश की सड़कों पर पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की जगह गन्ने के रस और मक्के से बनी ऊर्जा यानी एथेनॉल से गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आ सकती हैं। सरकार देश में फ्लेक्स-फ्यूल (स्नद्यद्ग&-स्नह्वद्गद्य) वाहनों को तेजी से उतारने की तैयारी कर रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता को खत्म किया जा सके। हालांकि, इस बड़े और क्रांतिकारी बदलाव से ठीक पहले भारत की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सरकार के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। वाहन निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हाई-एथेनॉल फ्यूल की कीमतें पेट्रोल के मुकाबले काफी कम नहीं की जातीं, तब तक आम ग्राहक इन नई और महंगी गाड़ियों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे।

क्या है श्व85 और श्व100 का गणित और क्यों उठ रही सस्ते ईंधन की मांग?

इस पूरे खेल को समझने के लिए श्व85 और श्व100 को जानना जरूरी है। श्व85 का मतलब है ऐसा ईंधन जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और मात्र 15 प्रतिशत पेट्रोल हो, जबकि श्व100 पूरी तरह से 100 प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल है। पेट्रोलियम मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (स्ढ्ढ्ररू) के बीच हुई चर्चा में यह बात साफ तौर पर उभरी है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा (श्वठ्ठद्गह्म्द्द4 ष्ठद्गठ्ठह्यद्बह्ल4) थोड़ी कम होती है, जिसका सीधा असर गाड़ी की माइलेज पर पड़ता है। ऑटो कंपनियों ने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां एथेनॉल, पेट्रोल से काफी सस्ता है, इसलिए लोग फ्लेक्स-फ्यूल वाहन धड़ल्ले से खरीदते हैं। भारत में भी ग्राहकों को फ्यूल के बिल में सीधी बचत दिखनी चाहिए, अन्यथा लोग मौजूदा श्व20 ईंधन से ही काम चलाते रहेंगे।

नई तकनीक से महंगी होंगी गाड़ियां, ऑटो इंडस्ट्री ने की टैक्स में भारी छूट की मांग

हाई-एथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल आम इंजनों में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम में बड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे, जिससे वाहनों की लागत अपने आप बढ़ जाएगी। इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी (त्रस्ञ्ज) में भारी कटौती की मांग की है। वर्तमान में इन वाहनों पर भी आम पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तरह 18 से 40 प्रतिशत तक टैक्स लगता है। हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों का मानना है कि भारत जैसे कीमत-संवेदनशील बाजार में शुरुआती दौर में टैक्स छूट मिलना बेहद जरूरी है। हालांकि, सरकार कारों पर टैक्स में बड़ी कटौती करने से हिचक रही है क्योंकि ऐसा करने से ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहनों (जिन पर मात्र 5त्न त्रस्ञ्ज है) की सीधी टक्कर में आ जाएंगी।

आखिर फ्लेक्स-फ्यूल और एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है सरकार?

सरकार का फ्लेक्स-फ्यूल पर इतना जोर देने का मुख्य कारण देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, जिस पर हर साल 120 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, जहां अक्सर तनाव के हालात बने रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में पेट्रोल की कुल मांग का लगभग 95-98 प्रतिशत और डीजल का 65-70 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। ऐसे में एथेनॉल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सीधे तौर पर देश का पैसा बचाएगा।

100त्न एथेनॉल का सपना और सामने खड़ी चुनौतियां

भारतीय मानक ब्यूरो (क्चढ्ढस्) ने हाई-एथेनॉल पेट्रोल के लिए नए तकनीकी मानक जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा मोटर्स से लेकर बजाज और होंडा तक तमाम ऑटो कंपनियों ने अपने फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता भी 20 अरब लीटर के करीब पहुंच चुकी है, जबकि मौजूदा मांग केवल 11 अरब लीटर के आसपास है। लेकिन इस राह में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। गन्ने से एथेनॉल बनाने में पानी की भारी खपत होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। ऐसे में नीति आयोग के पूर्व विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृषि कचरे यानी दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और ईंधन की जरूरत भी पूरी हो सके।

चीन की कोयला खदान में धमाका, 90 की जान गई, 247 मजदूर काम कर रहे थे

बीजिंग, एजेंसी। चीन के शांक्सी प्रांत में एक बड़े कोयला खदान हादसे में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं। यह बीते एक दशन में चीन का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह धमाका शुक्रवार को शांक्सी प्रांत के किनयुआन काउंटी की एक कोयला खदान में हुआ। यह इलाका राजधानी बीजिंग से करीब 520 किमी दूर है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ देर बाद जोरदार विस्फोट हो गया। उस समय खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके के बाद कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग अंदर फंस गए। अब तक 90 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राहत और बचाव दल लगातार लापता मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव टीमों को आदेश दिया कि वे लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

शांक्सी चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला प्रांत है। हालांकि चीन ने पिछले कुछ सालों में खदानों की सुरक्षा बेहतर करने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद हादसे रुक नहीं रहे हैं। फरवरी 2023 में इनर मंगोलिया की एक कोयला खदान में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 53 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं पिछले महीने शांक्सी के लुलियांग इलाके में भी खदान हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी। जिनपिंग ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और राज्यों को इस हादसे से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काम की जगहों पर सुरक्षा नियमों को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े हादसे न हों। उन्होंने यह भी कहा कि चीन में इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए बाढ़ और दूसरे प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए भी तैयारी मजबूत रखी जाए।

शांति वार्ता बेपटरी: अराघची बोले-अमेरिका की अत्यधिक मांगें बनीं रोड़ा, ईरान पर हमले को तैयार ट्रंप सेना?

तेहरान, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा कूटनीतिक गतिरोध अब एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। तेहरान ने वाशिंगटन पर शांति प्रयासों को पूरी तरह नाकाम करने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ फोन पर सीधी और विस्तृत बातचीत की है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका की अत्यधिक मांगें ही जारी शांति वार्ताओं और युद्धविराम समझौते के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट अल जजीरा के हवाले से सामने आई इस खबर के मुताबिक, विदेश मंत्री अराघची ने बातचीत के दौरान अमेरिका की नीयत पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने लगातार अपने वादों को तोड़कर, विरोधाभासी रुख अपनाकर और सैन्य आक्रामकता दिखाकर कूटनीतिक प्रयासों को हमेशा कमजोर किया है। अराघची ने कहा कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों और अमेरिकी दबाव की राजनीति के बावजूद तेहरान लगातार युद्धविराम वार्ताओं में सकारात्मक रूप से शामिल है और बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता तलाश रहा है। अराघची ने यह भी कहा कि एक तरफ सैन्य हमलों की धमकियां और दूसरी तरफ शांति का ढोंग, अमेरिका की यह विरोधाभासी और दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। ईरान अपनी संप्रभुता की कीमत पर अमेरिका के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा।

व्हाइट हाउस में हलचल और सैन्य हमलों की आहट

इस बीच सुरक्षा के मोर्चे पर एक बेहद सनसनीखेज और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य हमले करने की गंभीर योजना बना रहा है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से 'सीबीएस न्यूज' ने दावा किया है कि शुक्रवार को अमेरिकी प्रशासन ईरान पर हमलों के एक नए दौर की रणनीतिक तैयारियों में जुटा था। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इन हमलों को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

इस संभावित सैन्य कार्रवाई की खबर मिलते ही अमेरिकी सेना और खुफिया समुदाय के कई बड़े अधिकारियों ने अपने 'मेमोरियल डे वीकेंड' की छुट्टियां और प्लान तक रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यू जर्सी में अपने गोल्फ रिसॉर्ट पर वीकेंड बिताने और अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की और कहा कि देशहित और सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियों के कारण उनका इस समय व्हाइट हाउस में उपस्थित रहना बेहद जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र का रुख और शांति की अपील

दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के मुताबिक महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गुटेरेस ने स्पष्ट शब्दों में किसी भी देश की संप्रभुता के खिलाफ बल प्रयोग या सैन्य कार्रवाई के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए दोनों ही पक्षों से केवल और केवल कूटनीति का रास्ता अपनाने की पुरजोर वकालत की है।

'छात्र वीजा पर लगी पाबंदी से अमेरिका को पहुंच सकता है नुकसान', सांसद ने ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने ट्रंप प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए मौजूदा वीजा ढांचे को बनाए रखने का आग्रह किया है। वहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित प्रतिबंध अमेरिका की तकनीकी बढ़त, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान नेतृत्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर रस वॉट को भेजे गए एक पत्र में कांग्रेस के चार सदस्यों ने एफ-1 और जे-1 वीजा धारकों के लिए मौजूदा 'ड्यूरेशन और स्टेटस' स्थिति की अवधि) सिस्टम को एक तय चार साल की दाखिला की अवधि से बदलने के खिलाफ चेतावनी दी। इस पत्र पर प्रतिनिधियों सैम लिकार्डो, जे ओबरनोल्टे, मारिया सालाजार और राजा कृष्णमूर्ति ने हस्ताक्षर किए थे।

सांसदों ने क्या कहा?

सांसदों ने कहा कि मौजूदा सिस्टम 'संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबी अवधि की पढ़ाई, रिसर्च और वर्कफोर्स डेवलपमेंट' के लिए लचीलापन देता है, खासकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रोग्राम में, जहां डॉक्टरेट की पढ़ाई अक्सर छह साल से ज्यादा चलती है। सांसदों ने लिखा,अंतरराष्ट्रीय छात्र एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल रिसर्च और दूसरी उभरती टेक्नोलॉजी में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें निकाल देते हैं, तो वे अपने देश लौटकर विदेशी कंपनियों, जैसे चीन की कंपनियों को हमारे खिलाफ मुकाबला करने में मदद करेंगे।'

प्रशासनिक बोझ बढ़ेगी

अपने तीन पेज के पत्र में कांग्रेस सदस्यों ने तर्क दिया कि चार साल की सीमा कई छात्रों को बार-बार वीजा बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी, जिससे 'अनावश्यक प्रशासनिक बोझ, प्रोसेसिंग में देरी और शैक्षणिक निरंतरता में रुकावटें' आएंगी। उन्होंने सर्वे के डेटा का भी हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि लगभग आधे अंतरराष्ट्रीय स्नातक छात्र और पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई करना नहीं चुनते, अगर ऐसी कोई तय एडमिशन अवधि होती।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्रों का अहम योगदान

पत्र में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्रों के आर्थिक योगदान पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय छात्र हर साल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 43 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं और 355,000 से ज्यादा अमेरिकी नौकरियों में मदद करते हैं। सदस्यों ने लिखा, अमेरिकी व्यवसायों, सामानों और नौकरियों के अवसर बनाने के लिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय विद्वानों, छात्रों और नागरिकों की एक टीम की जरूरत होती है, जो अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी ताकत की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हों।'

6 से 11 प्रतिशत हिस्से का नुकासान हो सकता

सांसदों ने चेतावनी दी कि विदेशी एसटीईएम (STEM) ग्रेजुएट्स की संख्या में कमी से अमेरिकी वर्कफोर्स काफी कमजोर हो सकता है। पत्र में कहा गया, 'अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी एसटीईएम ग्रेजुएट्स की संख्या में एक-तिहाई भी कमी आती है, तो देश अपने उच्च-कुशल एसटीईएम वर्कफोर्स का 6 से 11 प्रतिशत हिस्सा खो सकता है।' इसमें आगे कहा गया कि ऐसी कमी से एक दशक के भीतर अमेरिकी जीडीपी में 'हर साल 240 डॉलर से 481 डॉलर बिलियन' की कमी आ सकती है।

सदस्यों ने माना कि प्रशासन विदेशी छात्रों पर ज्यादा कड़ी निगरानी रखना चाहता है और 'विदेशी विरोधियों को देश के विश्वविद्यालयों का गलत इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है'। लेकिन उन्होंने यह तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय छात्र पहले से ही 'सबसे अच्छी तरह से जांचे-परखे और लगातार निगरानी में रहने वाले गैर-आप्रवासी समूहों' में से हैं। सांसदों ने 'स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम' (एसईवीआईएस) का जिक्र किया, जो 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी' को विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स की 'लगातार, रियल-टाइम निगरानी' की सुविधा देता है।

प्राइवेट स्कूल एकेडमिक सेशन से पहले बिना सरकार की मंजूरी के बढ़ा सकते हैं फीस: कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्राइवेट स्कूल और बिना सरकारी सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपनी फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) की पूर्व अनुमति या मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये स्कूल DoE से पूर्व अनुमोदन के बिना शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फीस संरचना शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित की जाए। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे स्कूलों की एकमात्र वैधानिक बाध्यता सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस का पूरा विवरण शिक्षा निदेशालय के पास जमा करना है। कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा निदेशालय को बड़ा झटका लगा है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17(3) के तहत ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में फीस

वृद्धि लागू करने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि 'डीएसई अधिनियम की धारा 17(3) के तहत किसी निजी, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपनी फीस बढ़ाने के लिए किसी पूर्व अनुमति या मंजूरी की जरूरत नहीं है, और स्कूल पर एक मात्र वैधानिक दायित्व यह है कि उसे शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा निदेशालय के पास प्रस्तावित फीस का अपना विवरण दाखिल करना होगा'।

'पूर्व अनुमति केवल उसी स्थिति में जरूरी जब'

बेंच ने साफ किया कि पूर्व अनुमति केवल उसी स्थिति में जरूरी है, जब कोई स्कूल चालू शैक्षणिक सत्र के बीच अचानक फास बढ़ाना चाहता हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्कूल चल रहे शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाना चाहता है, तो DoE की पहले से मंजूरी ज़रूरी होगी। कोर्ट ने कहा कि DoE का रोल रेगुलेटरी है और यह पक्का करने तक ही सीमित है कि प्राइवेट स्कूल मुनाफ़ा कमाने, शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन करने या कैपिटेशन फीस लेने में शामिल न हों।

हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज की अगुवाई वाली कई याचिकाओं पर सुनाया, जिसमें DoE के फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज करने वाले कई आदेशों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा मामलों से यह साफ पता चलता है कि कैसे एक पब्लिक अथॉरिटी ऐसे काम पर अड़ी रह सकती है जो कानून के शब्दों और पहले से चली आ रही बातों, दोनों के प्रति जानबूझकर की गई बेपरवाही दिखाता है।कोर्ट ने कहा कि किसी स्कूल के फाइनेंशियल मामलों को कैसे चलाया जाए, यह तय करना या माइक्रो-मैनेज करना DoE का काम नहीं है।

स्कूलों ने कोर्ट में दिया तर्क

सुनवाई के दौरान स्कूलों ने तर्क दिया था कि DoE मनमाने ढंग से उनके फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को खारिज कर रहा है, जिससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के उनके अधिकार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और रूल्स के तहत, DoE फीस तय करने में तभी दखल दे सकता है, जब यह पाया जाए कि कोई स्कूल प्रॉफिट कमाने या कमर्शियलाइजेशन में शामिल है। कोर्ट ने इस बात को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी प्राइवेट, बिना मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए पहले से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि प्रस्तावित बढ़ोतरी चल रहे एकेडमिक सेशन के दौरान हो। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रॉफिट कमाने या कमर्शियलाइजेशन का नतीजा, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स के रूल 180 के तहत फाइल किए गए रिटर्न के आधार पर, एक्ट के सेक्शन 18(5) के तहत ऑडिट के बाद ही दिया जा सकता है।

'यह DoE का काम नहीं है'

जस्टिस भंभानी ने यह भी पाया कि DoE के ऑर्डर में प्रॉफिट कमाने या कमर्शियलाइज़ेशन का आरोप लगाने वाली कई बातें पक्के नतीजों पर आधारित नहीं थीं। कोर्ट ने उन्हें स्कूलों पर लागू अकाउंटिंग नियमों की DoE की गलत समझ से पैदा हुई बेवजह की बयानबाजी बताया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और रूल्स के तहत, प्राइवेट बिना मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। यह DoE का काम नहीं है कि वह यह तय करे या माइक्रो-मैनेज करे कि स्कूल अपने फाइनेंशियल मामले कैसे चलाते हैं। कोर्ट ने कहा, 'DSE एक्ट और DSE रूल्स के दायरे में, जैसा कि कोर्ट ने समझा है, एक प्राइवेट, बिना मदद वाले, मान्यता प्राप्त स्कूल को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, और यह DoE का काम नहीं है कि वह यह तय करे या माइक्रो-मैनेज करे कि स्कूल के फाइनेंशियल मामले कैसे चलाए जाएं'। इसके साथ ही कोर्ट ने DoE के लैंड क्लॉज़ से चलने वाले स्कूलों और ऐसे क्लॉज़ से नहीं चलने वाले स्कूलों के बीच के फर्क को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि भूमि खंड, जो आमतौर पर आवंटन पत्र में एक शर्त होती है, को अधिनियम और नियमों के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए और यह शिक्षा विभाग की वैधानिक शक्तियों को बढ़ा नहीं सकता है।

'इसे मुनाफाखोरी' नहीं कहा जा सकता'

कोर्ट ने आगे कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को भविष्य की वृद्धि और विकास सहित वैध जरूरतों के लिए धन का उचित अधिशेष बनाए रखने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूलों ने तर्क दिया था कि इस तरह के अधिशेष धन के रखरखाव को शिक्षा निदेशालय द्वारा 'मुनाफाखोरी' नहीं कहा जा सकता है, कोर्ट भी इस तर्क से सहमत हुआ।

कोर्ट ने कहा कि किसी निजी, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल के पास अधिशेष धन की उपलब्धता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, शिक्षा निदेशालय के लिए यह अनुमान लगाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि स्कूल व्यवसायीकरण या मुनाफाखोरी में लिप्त है और इस तरह स्कूल द्वारा फीस वृद्धि पर आपत्ति जताई जा सकती है। व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी के पहलू की जांच और निर्धारण शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी स्कूल का पूर्ण वित्तीय ऑडिट करने के बाद ही किया जा सकता है।

पिछले एकेडमिक सेशन का बकाया वसूलने की इजाजत नहीं

लेकिन, हाईकोर्ट ने स्कूलों को पिछले एकेडमिक सेशन का बकाया वसूलने की इजाज़त देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रपोज़ल 2016-17 के हैं और अब वसूली की इजाजत देने से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा और मंजूर बोझ पड़ेगा। इसलिए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूलों द्वारा प्रस्तावित पिछली फ़ीस बढ़ोतरी अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले अगले एकेडमिक सेशन से ही लागू होगी। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी स्कूल पिछले एकेडमिक सेशन का बकाया पिछली तारीख से नहीं मांग सकता या वसूल नहीं कर सकता।

सोशल मीडिया पर छाया मेलोडी का खुमार, कृति खरबंदा ने टॉफी वाली पोस्ट से लूट ली महफिल!

सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नाम को मिलाकर मेलोडी ट्रेंड छाया हुआ है। इस मजेदार मीम फेस्ट में अब अभिनेत्री कृति खरबंदा भी शामिल हो गई हैं। कृति ने इंस्टाग्राम पर भूरे (ब्राउन) रंग की खूबसूरत ड्रेस में अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसका रंग बिल्कुल मेलोडी टॉफी से मिल रहा है। अभिनेत्री ने मजा लेते हुए कैप्शन भी कुछ ऐसा डाला कि सभी का ध्यान उनके कैप्शन की ओर खींचा चला गया। कृति लिखती हैं, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? कृति की पोस्ट सभी को बहुत पसंद आ रही हैं। उनके फैंस कमेंट सेक्शन पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि मेलोडी शब्द को सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर इस्तेमाल करके वैश्विक मंचों पर इन दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत को हाईलाइट करते हैं।

इस वायरल ट्रेंड को तब रफ्तार मिली, जब इटली के दौरे पर पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर मेलोडी चॉकलेट/टॉफी गिफ्ट की थी। मेलोनी ने इस क्यूट जेस्चर के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जो इंटरनेट पर आते ही छा गया।

इस मजेदार ट्रेंड के साथ-साथ यह ऑनलाइन ट्रेंड दोनों देशों के बीच मजबूत हो रही कूटनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को भी प्रदर्शित करता है। अभिनेत्री कृति खरबंदा पिछली बार फिल्म राणा नाइडू-2 में नजर आई थी। यह एक एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म है।

अभिनेत्री हाल ही में फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आई थीं। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, सौंदर्या शर्मा और आकाशदीप साबिर जैसे स्टार्स शामिल हैं।

फिल्म मां बहन के किरदारों का हुआ नामकरण, निर्माताओं ने बताया आज आएगा ट्रेलर

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी अपनी फिल्म मां बहन के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी करते हुए सभी किरदारों से रूबरू करवाया था। फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट आया है, जिसमें इन किरदारों का नामकरण किया गया है। इसके अलावा, ट्रेलर की रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया गया है। बता दें, इस डार्क कॉमेडी का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है। नए वीडियो क्लिप में, माधुरी का कॉलोनी रानी रेखा के तौर पर परिचय कराया गया है। बेटी बनीं तृप्ति सयानी रानी जया के किरदार में हैं। दूसरी बेटी का किरदार धर्णा दुर्गा निभा रही हैं, जिन्हें रील्स रानी सुषमा के तौर पर पेश किया गया है। रवि किशन भी इसका हिस्सा हैं और वह आदर्श पुरुष गुप्ता के किरदार में हैं। फिल्म का ट्रेलर आज 22 मई को रिलीज किया जाएगा, जबकि फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

वहीं फिल्म की कास्ट ने प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। माधुरी दीक्षित इस दौरान सफेद रंग की साड़ी में नजर आईं, इसमें काले रंग से हल्की सी कढ़ाई भी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ऊपर से ब्लैक कलर का ब्लेजर भी डाल रखा है, जो उनके लुक को कंप्लीट करता है। कानों में बड़े से ईयररिंग्स पहने माधुरी काफी स्टनिंग लग रही थीं। 'मां बहन का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है। यह एक मोहल्ले की कहानी है। फिल्म में माधुरी और तृप्ति के अलावा रवि किशन, धरना दुर्गा, गीतांजलि कुलकर्णी और अरुणोदय सिंह जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'मां बहन 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी है।

बंदर का ट्रेलर रिलीज, शोहरत और अकेलेपन के जाल में फंसे बॉबी देओल

एनिमल की अपार सफलता के बाद बॉबी देओल एक बार फिर पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म बंदर दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में बॉबी एक ऐसे सुपरस्टार के किरदार में हैं, जो शोहरत के चरम पर होने के बावजूद अकेलेपन, गहरे शक और मानसिक द्वंद्व से जूझ रहा है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ट्रेलर में बॉबी देओल का लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

बंदर का 2 मिनट से ज्यादा लंबा ट्रेलर सस्पेंस, चौंकाने वाले ट्विस्ट्स और अनुराग कश्यप के गंभीर दृश्यों में छुपे अनोखा व्यंग्य से भरपूर है। बॉबी एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में दिख रहे हैं, जो शोहरत की बुलंदियों पर तो है, लेकिन पर्दे के पीछे अकेलेपन, गहरे शक और मानसिक तनाव के एक बेहद परेशान करने वाले जाल में फंसा हुआ है। पल-पल बदलते हालात और तनाव से भरे इस ट्रेलर में बॉबी बेहद दमदार नजर आ रहे हैं।

फिल्म का ट्रेलर पूरी तरह से बॉबी के एक चौंकाने वाले किरदार के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें बॉबी एक ऐसे कलंकित और पुराने सुपरस्टार के रूप में नजर आ रहे हैं, जो जनता के सामने तो बेहद करिश्माई दिखता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अकेलेपन से जूझ रहा हैगमम। कहानी धीरे-धीरे उसकी चमक-धमक भरी दुनिया से एक अंधेरी हकीकत की तरफ मुड़ती है, जहां रहस्य गहराने के साथ ही यह सुपरस्टार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।

ट्रेलर में खासकर बॉबी की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। एक ने लिखा, बॉबी एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने किरदार को जी रहे हैं। कुछ का कहना है कि अनुराग और बॉबी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला

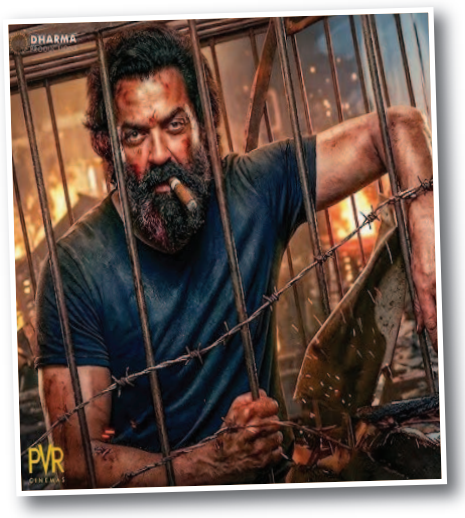

देगी। इस फिल्म की कहानी को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की जोड़ी ने लिखा है। ये वही हिट जोड़ी है, जो इससे पहले पाताल लोक, कोहरा और उड़ता पंजाब जैसे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स लिख चुकी है।

बंदर में बॉबी के साथ एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकारों की फौज नजर आने वाली है। फिल्म में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, ऋद्धि सेन और जितेंद्र जोशी जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं। निखिल द्विवेदी की कंपनी सैफ्रन मैजिकवर्क्स द्वारा प्रोड्यूस और रंश्वश्व स्टूडियोज के सहयोग से बनी ये सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। फिल्म के ट्रेलर ने इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

फिल्म रजनी की बारात का ट्रेलर जारी, उल्का गुप्ता की नए अंदाज में वापसी

बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी 2 में उल्का गुप्ता ने अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में वह एक पढ़ी-लिखी हिंदू महिला के किरदार में थीं, जो मुस्लिम युवक के झांसे में आकर धर्म बदल लेती है। अब वह एकदम अलग तरह का किरदार लेकर दर्शकों के बीच लौट रही हैं। उनकी आगामी फिल्म रजनी की बारात का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो बिहार के दरभंगा शहर की पृष्ठभूमि पर बनी है।

आदित्य अमन द्वारा निर्देशित फिल्म का ट्रेलर रोमांस, कॉमेडी, और मेलोड्रामा से भरपूर है। कहानी रजनी (उल्का) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मनपंसद शादी के लिए किस्मत और समाज के नियमों को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वह बारात का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर शादी करने निकल पड़ती है। पंचायत सीरीज वालीं अभिनेत्री सुनीता राजवार और जरीना वहाब भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म 29 मई को

सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

एपीफ़ेनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता तनाया आडारकर और तेज एच आडारकर हैं, जबकि निर्देशन आदित्य अमन ने किया है। फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर मोहसिन खान हैं।

फिल्म में उल्का गुप्ता, कनिष्क, इशिता सिंह, सुनीता राजवार, ज़रीना वहाब और अश्वथ भट्ट प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फ़िल्म की शूटिंग बिहार के दरभंगा और मिथिलांचल के खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है।

ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अभिनेत्री उल्का गुप्ता ने कहा, रजनी एक ऐसी लड़की है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस किरदार में इमोशन, कॉमेडी और पागलपन सब कुछ है। रजनी बिहार की एक ऐसी लड़की को रिप्रेजेंट करती है, जो अपने दिल की सुनती है और हर चुनौती का सामना करने का हौसला रखती है। इस रोमांटिक और इमोशनल कहानी में कॉमेडी और ड्रामा दर्शकों को बहुत इंट्रेस्टिंग अनुभव देगा।

फिल्म की निर्माता तनाया आडारकर ने कहा, रजनी की बारात सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह परिवार, रिश्तों, सपनों और एक लड़की के जुनून की कहानी है। हमने फिल्म को पूरी तरह देसी फ्लेवर और मनोरंजन के साथ बनाया है। ट्रेलर में जो अराजकता, कॉमेडी और ड्रामा दिखाई देता है, वह फिल्म का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। हमें विश्वास है कि दर्शक रजनी और उसकी इस अनोखी बारात से खुद को जोड़ पाएंगे। 'रजनी की बारात' 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com